● वर्ष-2
● अंक-286
रायपुर, शनिवार
22 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का होगा सर्वेक्षण

वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे के पक्ष में दिया फैसला

नईदिल्ली। वाराणसी जिला अदालत शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद क्षेत्र को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण की मांग करने वाली एक अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले में एएसआई के सर्वे की इजाजत मिल गई है। विवादित परिसर को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था।

श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में चार हिंदू महिला वादी के वकील विष्णु शंकर जैन ने 16 मई को जिला अदालत में आवेदन दायर किया। बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई। श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के विशेष वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि अदालत ने ज्ञानवापी के बैरिकेड क्षेत्र में एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाले आवेदन में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। इससे पहले अदालत ने मामले में अपना आदेश 21 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू पक्ष का दावा

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है और केवल एक आदेश पारित किया जा

रहा है। दूसरे पक्ष द्वारा एएसआई सर्वेक्षण की मांग की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर के गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर के अवशेष हैं। इसके अलावा, मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर के अवशेष हैं। जैन ने दावा किया कि सील क्षेत्र को छोड़कर, ज्ञानवापी के बैरिकेड क्षेत्र में एएसआई सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। वादी संख्या एक राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने एएसआई से सर्वे कराने की मांग का समर्थन किया।

मुस्लिम पक्ष का विरोध

एआईएमसी के वकील एखलाक अहमद ने ज्ञानवापी के बैरिकेडिंग क्षेत्र में सर्वेक्षण की मांग के खिलाफ दलील दी। उनकी तरफ से कहा गया कि नया सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण मई 2022 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के आदेश पर अधिवक्ता आयुक्त द्वारा पहले ही किया जा चुका था। उस मामले का निपटारा नहीं हुआ है. इसलिए नये सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है। केंद्र के स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव भी अदालत में मौजूद थे।

6 महीने में पूरा हो सकता है सर्वे

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है। वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए। शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा।

कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब रास्ता भारत से

भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी मिली है। शिवधाम यानी कैलाश पर्वत पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के लिपुलेख में रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे जल्द ही शुरू किया जा सकता है। समाचार एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि इस साल सितंबर के बाद से श्रद्धालुओं को भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन भारतीय भूभाग से सुलभ हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पिथौरागढ़ जिले के नाभीढांग में केएमवीएन हटस से भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक सड़क की कटाई का काम शुरू कर दिया है जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा।

बीआरओ की हीरक परियोजना के मुख्य अभियंता विमल गोस्वामी ने कहा, '' हमने नाभीढ़ांग में केएमवीएन हटस से लिपुलेख दर्रे तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क को काटने का काम शुरू कर दिया है। सड़क का काम पूरा होने के बाद सड़क के साथ-साथ 'कैलाश व्यू प्वाइंट' तैयार होगा। '' हीरक परियोजना को भारत सरकार ने 'कैलाश व्यू प्वाइंट' विकसित करने की जिम्मेदारी दी है। गोस्वामी ने बताया कि सड़क की कटाई का काफी काम हो चुका है और अगर मौसम अनुकूल रहा तो यह सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क की कटाई के बाद 'कैलाश व्यू प्वाइंट' बनाने का काम होगा।

इन दिनों

जितेंद्र भारद्वाज

महिलाओं से बलात्कार राजस्थान और छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के प्रति कठोर कदम उठाने की अपील करते हुए कहा, घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान मणिपुर में यौन हिंसा का वीडियो वायरल होने के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा हृदय आज पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले कितने हैं और कौन हैं, ये अपनी जगह है। ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में 2021 के दौरान 6337 रेप के मामले दर्ज हुए थे। रेप का यह आंकड़ा, किसी भी राज्य में सर्वाधिक रहा है। छत्तीसगढ़ में रेप की 1093 घटनाएं हुई थीं। मध्यप्रदेश में 2947, यूपी में 2845 और महाराष्ट्र में यह संख्या 2496 रही है। देश में पांच वर्ष यानी 1825 दिनों में डेढ़ लाख महिलाओं से बलात्कार हुआ है। यानी रोजाना 87 महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक, बलात्कार की घटना वाले टॉप-10 राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। साल 2020 की रिपोर्ट में भी छत्तीसगढ़, टॉप-10 स्टेट में शामिल नहीं है। हालांकि राजस्थान, 2021 और 2020 में रेप की घटनाओं में टॉप पर रहा है। 2019 के दौरान भी राजस्थान में ही बलात्कार के सर्वाधिक 5997 मामले सामने आए थे। साल 2018 में राजस्थान, टॉप पर नहीं था। उस वक्त मध्यप्रदेश, बलात्कार के 5433 मामलों के साथ टॉप पर था। राजस्थान का नंबर दूसरा था। साल 2017 में भी मध्यप्रदेश बलात्कार के मामलों में टॉप पर रहा। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का था। तीसरे स्थान पर राजस्थान था। साल 2021 में देश में रेप के कुल 31677 मामले सामने आए थे। वर्ष 2020 में बलात्कार की 28046 घटनाएं हुई थीं। अगर पीड़ितों की संख्या देखें, तो वह आंकड़ा 28153 रहा है। साल 2019 में रेप के 32033 मामले देखने को मिले थे। इनमें पीड़ित महिलाओं की संख्या 32260 रही है। वर्ष 2018 में रेप के कुल 33356 मामले सामने आए थे। पीड़ितों की संख्या 33977 रही है। साल 2017 के दौरान बलात्कार के 32559 केस देखने को मिले थे। इन मामलों में पीड़ितों की संख्या 33658 रही है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पांच साल के दौरान 159048 से अधिक रेप के मामले सामने आए हैं। राजस्थान के मंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की स्थिति खराब है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या छत्तीसगढ़ में खराब नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान पर राजनीति करने बजाय समस्या का समाधाम करने में ध्यान दें तो देश में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर अंकुश लग सकेगा।

मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो के दो दिन बाद, स्थानीय लोगों ने वायरल वीडियो में देखे गए कथित आरोपियों में से एक ह्यूरिम हेरादास सिंह के घर में आग लगा दी।

ममता महिलाओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रोक रही: लॉकेट

- **कैमरे के सामने ही फूट-फूट कर रोने लगीं बीजेपी सांसद, बंगाल भी इसी देश में**

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान एक भाजपा उम्मीदवार के टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा यौन उत्पीड़न की कथित घटना को याद करते हुए भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी भावुक हो गई। लॉकेट चटर्जी एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि क्या हम महिला नहीं, बंगाल में बदसलूकी हुई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक के बाद एक घटना घट रही है मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला होने बाद भी चुप हैं। उन्होंने

कहा कि आप बताइए हम लोग कहां जाएंगे। हम लोग भी महिला हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को बचाया जाए। मणिपुर की बेटी भी देश की बेटी है, पश्चिम बंगाल भी देश में हीं है।

भाजपा सांसद ने कहा कि बंगाल में पंचायत के चुनाव नहीं बल्कि खून के चुनाव हुए। इसमें बहुत हिंसा और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ वह उतना ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव पंचायत चुनाव नहीं बल्कि खून का चुनाव% रहे हैं। ये चुनाव महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा और अत्याचार के एक शर्मनाक दौर के अलावा और कुछ नहीं थे।

सुकांता मजुमदार का दावा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि बंगाल में कुछ दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई वह आप सबको पता है। उन्होंने कहा कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है, लेफ्ट के शासनकाल में भी वहां हिंसा होती थी। मजुमदार ने कहा कि 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को अपनी सरकार आने के बाद आश्वासन दिया था कि ये हिंसा बंद होगी, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ बल्कि ममता जी की सरकार में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि हमारे बूथ एजेंट के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

प्रमुख समाचार

राहुल गांधी की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के पूर्व मंत्री

पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने मामले में राहुल की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने राहुल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख तय की। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा के दौरान 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। पीठ ने कहा, इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।

गहलोत सरकार के मंत्री बोले- हम महिला सुरक्षा में विफल

नईदिल्ली। मणिपुर से नग्न महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर क्रोध व्यक्त किया था और कहा था कि राज्य सरकारों को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान का भी नाम लिया था। दरअसल, जोधपुर में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रही है। ऐसे में भाजपा राजस्थान में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इन सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे की पोल उनकी सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ही खोल दी है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यह सच है और इसे स्वीकार करना चाहिए कि हम महिला सुरक्षा में विफल रहे हैं। मणिपुर के बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। वीडियो राजस्थान विधानसभा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है।

मणिपुर मामले में एक्शन, 4 आरोपियों को पुलिस कस्टडी

इंफाल। मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड की घटना मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 4 मई की

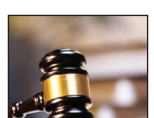

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें राज्य में दो समुदायों के बीच अशांति के बीच मणिपुर में 2-3 महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। इस घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है और कहा है कि यह देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि आरोपियों से सख्ती से निपटा जाएगा और वे मौत की सजा पर भी विचार कर रहे हैं। यह वीडियो, जो बुधवार को सामने आया, कथित तौर पर 4 मई को कांगपोकपी इलाके में एक बैठक के दौरान राज्य में हुए हंगामे के एक दिन बाद शूट किया गया था। पुरुषों के एक समूह ने दो कुकी-ज़ोमी महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी रखा, जबकि उन्हें वीडियो में नग्न परेड कराया

सीमा हैदर के बहाने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले

नई दिल्ली। देश के एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह के अनुसार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू व्यवसायी की तीन बेटियों की शादी मुस्लिम पुरुषों से की गई है, जिन्होंने पहले

उनका अपहरण किया और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। पाकिस्तान दरेवर इतेहाद के प्रमुख शिव काछी ने कहा कि यह घटना सिंध के ढरकी इलाके में हुई जहां एक हिंदू व्यापारी लीला राम की बेटियों चांदनी, रोशनी और परमेश कुमारी का पहले अपहरण किया गया और फिर उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। धर्मांतरण एक पीर जावेद अहमद कादरी द्वारा किया गया था और बाद में उनकी शादी भी मुस्लिम पुरुषों से कराई गई थी। काछी ने कहा कि उनके संगठन के मंच से अपील और दलीलों के बावजूद, हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की समस्या बदस्तूर जारी है और पुलिस और अधिकारी दोषियों को नहीं पकड़ रहे हैं। तीनों बहनों की शादी उन्हीं पुरुषों से हुई थी, जिन्होंने उनका अपहरण किया था। काछी ने यह भी दावा किया कि सीमा हैदर घटना के बाद से नदी क्षेत्रों में हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं।

चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के एक कदम करीब

बेगलुरू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान की चौथी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस महत्वपूर्ण विकास की घोषणा गुरुवार को इसरो द्वारा

की गई। इसे भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अर्थ-बाउंड पेरिगी फायरिंग के रूप में जाना जाने वाले प्रैक्टिस को बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवक से किया गया था। यह उपलब्धि चंद्रयान-3 को उसके अंतिम गंतव्य - चंद्रमा के करीब ले जाती है। चल रहे मिशन ऑपरेशन के हिस्से के रूप में अगली फायरिंग 25 जुलाई, 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे ढ्ढस्ञ्ज के बीच निर्धारित की गई है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई, 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्न्ड्डस्ङ्क-स्ढ्ढ रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।चंद्रयान-3 को 14 जुलाई, 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्न्ड्डस्ङ्क-स्ढ्ढ रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण के सत्रह मिनट बाद, उपग्रह को उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। चौथे कक्षा-उत्थान पैंतरेबाज़ी का सफल निष्पादन तीसरे के बाद होता है, जिसे इस सप्ताह के शुरू में भी सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था।

चुनावी तैयारी में कोई ढील नहीं देगी भाजपा

नीरजा चौधरी

भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस सप्ताह एनडीए का पुनर्गठन किया और 38 दलों को गठबंधन में जुटा लिया उससे एक बात स्पष्ट है, कि भाजपा चेतावनी के किसी भी संकेत को बहुत गंभीरता से लेती है। विपक्ष की ओर से पिछले महीने पटना बैठक के बाद एकजुटता की जो कोशिशें हुई हैं, उन्हें भाजपा गंभीरता से ले रही है। भाजपा का अकेले अपने दम पर चुनाव में उतरने का पुराना रवैया अब बदल चुका है। भाजपा अब जोखिम नहीं लेना चाहती और कोई भी ढील नहीं देना चाहती। वर्ष 2019 के पिछले चुनाव में भाजपा ने अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। उत्तर भारत में उसने 90 फीसदी से ज्यादा सीटें हासिल की थी। ऐसे में अगर अगले चुनाव में विपक्ष की एकता की वजह से भाजपा की 60-70 सीटें कम हो जाती हैं तो उनके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसी खतरे को ध्यान में रख वह अपने सहयोगियों को दोबारा जुटा रहे हैं या एनडीए का पुनर्गठन कर रहे हैं या उसका विस्तार कर रहे हैं, ताकि यदि कहीं वे बहुमत के आंकड़े से दूर रह गये तो अपने उन सहयोगियों का सहारा ले सकें।

हालांकि, भाजपा ने जिन 38 दलों को जुटाया है, उनमें ज्यादा पार्टियां बहुत छोटी हैं। मगर उनका महत्व तो होता ही है। जैसे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा है या संजय निषाद की निषाद पार्टी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन राजभर और निषाद जैसे छोटे समुदायों का चुनाव में अपने इलाकों में काफी महत्व होता है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की बैठक में एनडीए के

बारे में बहुत ही जोर-शोर से बातें की और कहा कि 25 सालों से एनडीए कायम है, और इसी की वजह से उनकी सरकार ने कई काम किये। इस बैठक में प्रधानमंत्री का रुख बिल्कुल अलग था, जिसमें उनका गठबंधन की तरफ झुकाव नजर आया। एनडीए के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर आयेगी। आगे बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जमीनी स्तर पर लोगों की भावनाएं कितनी बदल रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दे चुनाव में कितना असर डालते हैं, और दस साल के बाद क्या कोई सत्ता-विरोधी लहर बन पाती है, यह सब आगे चलकर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहां यह भी देखना होगा कि विपक्ष के पास क्या ऐसी सांगठनिक क्षमता है जिससे वह इन भावनाओं को मुद्दा बना सके। क्योंकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका मुकाबला एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ है जिसके पास एक लोकप्रिय नेता और एक बहुत ही मजबूत संगठन है। एनडीए के सामने दूसरी बड़ी चुनौती विपक्ष की एकजुटता की होगी। विपक्षी दलों में यदि सीटों के बंटवारे पर सहमति हो जाती है और चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के सामने विपक्ष का केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है तो वह कड़ा मुकाबला हो जायेगा। ध्यान रहे कि पिछले चुनाव में 63 फीसदी मत गैर-भाजपा दलों के खाते में गये थे।

भाजपा को 2019 के चुनाव में 37 प्रतिशत वोट मिले थे। हालांकि, यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी चार-पांच बड़ी पार्टियां किसी भी पाले में नहीं हैं। इनमें नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाइएसआर कांग्रेस और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां हैं। यह संभव है कि अंदरखाने भाजपा के साथ इनकी कोई सहमति हो गयी हो, मगर अभी तक ये किसी एक पाले में नहीं गयी हैं। ये पार्टियां 2024 के चुनाव में जो भी सत्ता में आता दिखेगा, उसके साथ जा सकती हैं। बाकी की सारी पार्टियां एनडीए को चुनौती देने के लिए जुटे विपक्ष का हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि, अभी कुछ भी अंतिम नहीं है। आने वाले दिनों में अक्सर ऐसी खबरें आयेंगी कि किसी पार्टी में टूट हो गयी, तो कुछ पार्टियां एकजुट हो गयीं। एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए अभी सबसे दिलचस्प बिहार हो गया है। वहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट की अटकलें लगायी जा रही हैं। चिराग पासवान को एनडीए में लौटाकर भाजपा ने बड़ा हाथ मारा है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद विपक्ष को झटका जरूर लगा है। लेकिन, चुनाव के समय एनसीपी क्या करेगी यह कहना मुश्किल है। मान लें कि यदि अजित पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो क्या वह शरद पवार के पास लौट सकते हैं? वहीं यदि पवार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या एकनाथ शिंदे वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जायेंगे? ये सभी संभावनाएं बरकरार हैं और चुनाव के आस-पास समीकरण बदलेंगे।

सहकारी समितियों के बीज से कम हो रहा अंकुरण, किसान परेशान

गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ सरकार एवं बीज निगम द्वारा आदिवासी सेवा सहकारी समितियों में किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए उन्नत किस्म के बीज किसानों के लिए बेकार साबित हो रहे हैं, खेतों में रोपा लगाने के पहले किसानों द्वारा तैयार की जाने वाली धान की नर्सरी में यह बीज जम ही नहीं रहे हैं। जो भी क्षेत्रों में जम रहे हैं उनका प्रतिशत भी 40 से 50% ही है ऐसे में समय व्यतीत होने के साथ किसानों को खेती में नुकसान होने का डर सता रहा है।

मानसून की बारिश होने के पहले ही किसान धान की फसल के लिए खेतों को तैयार करना शुरू कर देते हैं। वहीं, बारिश होने के पहले उन्नत किस्म के बीज खरीदते हैं ज्यादातर किसान छत्तीसगढ़ शासन बीज निगम द्वारा सहकारी समितियों में आपूर्ति किए गए उन्नत किस्म के बीजों का ही चयन करते हैं क्योंकि इन बीजों की उत्पादन क्षमता के साथ-साथ रोगों से लड़ने की क्षमता परंपरागत बीजों से अधिक होती है। पर इस बार पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराए गए उन्नत किस्म के बीज जिसमें 1010 किस्म का धान शामिल है, जिसे क्षेत्र के लोग बहुतायत में बोते हैं। जब इस बार किसान 1010 किस्म के धान बीज की नर्सरी तैयार करने के लिए उसे खेतों में बोया गया तब इन बीजों का अंकुरण

40 से 50% ही हुआ जबकि कुछ किसानों के खेतों में इसका अंकुरण और भी कम रहा।

जिसकी वजह से किसान अब दोहरी मार झेलने को विवश हैं क्योंकि जहां एक तरफ उनके द्वारा बोले गए बीज बेकार साबित हो रहे हैं तो वहीं धान बुवाई का समय भी तेजी से बीतता जा रहा है। अब किसान को मजबूरी में अधिक उपजाऊ रोपा पद्धति को छोड़कर सुखी बुआई करना होगा पर इसमें किसानों को धान के उत्पादन का नुकसान तो होगा ही साथ ही खेती के लिए नए बीजों का भी करना पड़ेगा। वही इस पद्धति से धान लगाने पर रोग लगने का खतरा भी अधिक होता है। यही हाल खुले बाजार से खरीदे गए इस किस्म के धान का भी है खुले बाजार से खरीदे गए किसान भी इन बीजों के कम अंकुरण से परेशान हैं।

धान के अच्छे उत्पादन के लिए किसान अधिक मूल्य पर सहकारी समितियों से उन्नत किस्म के बीज खरीदता है ताकि उसकी फसल रोगमुक्त हो एवं उत्पादन भी अच्छा हो पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, इस पूरे मामले की जानकारी कृषि विभाग के पास भी है उन्होंने कुछ किसानों के बीज का सैंपल भी लिया है। लगभग 80 सैंपल में से 10 सैंपल की रिपोर्ट आई है विभाग का कहना है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है पर फिर भी उसे बाकी रिपोर्ट का इंतजार है। पर किसानों को अब जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करने के लिए विभाग के पास भी कोई कार्य योजना नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग एवं बीज निगम की जिम्मेदारी है कि किसानों को उन्नत किस्म के बढ़िया बीज को उपलब्ध कराएं। लेकिन किसान जिस तरह घटिया बीजों को पाकर इस बार परेशान हुए हैं उससे स्पष्ट है कि बीज निगम ने अपना काम कितनी शिद्दत से किया है। अब किसानों को होने वाले नुकसान के संबंध में विभाग एवं सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि किसान इस तरह के नुकसान की भरपाई हो सके।

आईएएस रानू साहू और कई व्यवसायियों के घर ईडी की छापा

अंबिकापुर। ईडी की टीम ने एक बार फिर राज्य के तीन शहरों में शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर के अलावा बिलासपुर व कोरबा में टीम पड़ताल कर रही है। इनमें नेताओं,अफसरों व ठेकेदारों के निवास व आफिस में जांच की जा रही है। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय की जांच संभाग मुख्यालय अंबिकापुर तक पहुंच गई है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को ब्रम्हरोड के सेठ बसंतलाल गली स्थित व्यवसायी अशोक कुमार अग्रवाल के निवास पर दबिश दी। दो वाहनों में पहुंचे ईडी की टीम ने व्यवसायी के घर से पहुंचकर जांच शुरू की।

बताया जा रहा है कि व्यवसायी बड़े सप्लायर हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई का काम करते हैं। ईडी की टीम ने आज आईएएस दंपती रानू साहू, जेपी मौर्य के साथ ही व्यवसायियों के दर्जनभर ठिकानों पर आज सुबह जांच शुरू की है। उधर, कोरबा के नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। पांच सदस्यीय टीम ने शुक्रवार सुबह पांच बजे छापा मारा। टीम दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की पांच सदस्यीय टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान आए हुए हैं, जो घर के अंदर-बाहर तैनात हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रवर्तन

निदेशायल की टीम शुक्रवार सुबह अंबिकापुर पहुंची और सेठ बसंतलाल मार्ग में स्थित व्यवसायी अशोक अग्रवाल के घर पहुंची। इस टीम में महिलाएं भी हैं। ईडी की टीम ने अशोक अग्रवाल के घर पहुंचकर जांच शुरू की। वहां से टीम उनके सत्तीपारा कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंची व दस्तावेज खंगाले। बताया जा रहा है कि अशोक अग्रवाल प्रदेश में बड़े पैमाने पर सप्लाई का काम करते हैं। मुख्य रूप से इनके सप्लाई का काम शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई का काम करने वाले अशोक अग्रवाल के घर छापे का कनेक्शन एकीकृत आदिवासी परियोजना व डीएमएफ मद से सप्लाई से जुड़ा बताया गया है। आशंका है कि यहां ईडी की टीम ने उनके निवास से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी की टीम अशोक अग्रवाल के ठिकानों में छापेमारी के बाद अन्य व्यवसायियों के घर भी छापेमारी कर सकती है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सासंद कार्यालय का किया घेराव, महंगाई के खिलाफ की नारेबाजी

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में महंगाई के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। महिला कांग्रेस ने रैली निकालकर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय के कार्यालय के घेराव किया और जमकर नारे-बाजी की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानू मनोज दुबे ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सांसद कार्यालय के घेराव का आह्वान किया था। दोपहर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सिग्नल चौक स्थित कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए। महिला कार्यकर्ताओं का साथ देने कांग्रेस कार्यकर्ता भी कांग्रेस भवन पहुंचे।

यहां पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में बेलगाम महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सौ दिनों में महंगाई कम करने के मुद्दे पर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। सरकार अपने वायदे को भूल गई और बढ़ती महंगाई से अपनी आंख को मूंद कर बैठी है। इसके चलते देश का प्रत्येक नागरिक परेशान है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं बढ़ती महंगाई से मची है हाहाकार, कुंभकरणी नींद में सोई है मोदी सरकार के नारे के साथ ही नींद से जागों मोदी सरकार के नारे लगाए।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को दिखाने के लिए अपने गले में टमाटर की माला पहनी। टमाटर की महंगाई का आलम ये है कि इसका दाम डेढ़ सौ रुपये किलो हो गया है। खाने-पीने की जरूरी वस्तुएं पहले ही आसमान छु रही थी। अब टमाटर के महंगे हो जाने से हर परिवार का मासिक बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई के मुद्दे पर सांसद संतोष पांडेय की लगातार चुप्पी पर भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा प्रकट किया।

पुलिस की रही तगड़ी सुरक्षा

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सांसद कार्यालय के आस-पास बैरीकेड लगाकर भारी सुरक्षा-व्यवस्था कर रखी थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। महिला कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए महिला पुलिस बल तैनात किया गया था।

कन्हर नदी पर अवैध रेत परिवहन खनिज और राजस्व टीम ने की कार्रवाई

बलरामपुर। जिला की राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले में कई दिनों ने कन्हर नदी से अवैध रेत खनन की शिकायत मिल रही थी ।जिसके बाद विभाग ने टीम बनाकर बड़ी कार्रवाई की है। कन्हर नदी में रेत का अवैध खनन और परिवहन करते टीम ने वाहनों को जब्त किया है। जिसमें चार ट्रैक्टर शामिल हैं।

राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई- कन्हर नदी से अवैध रेत उत्खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कन्हर नदी के रेत घाट पर पहुंचकर जांच की गई । जिसमें टीम ने रेत माफिया के चार ट्रैक्टर को जब्त किया है। जिनमें मजदूर लगाकर रेत को लोड किया जा रहा था।

खतरे में कन्हर नदी का अस्तित्व- अवैध रेत उत्खनन करने से नदी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। रामानुजगंज में कई रेत घाटों से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी के रेत उत्खनन कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। एनजीटी की रोक के बावजूद लगातार रेत उत्खनन होने से नदी अपना अस्तित्व खोते जा रही है।

आपको बता दें कि बलरामपुर जिले की जीवनरेखा कही जाने वाली कन्हर नदी पर अवैध रेत खनन हो रहा था ।रोजाना अवैध खनन के बाद दो सौ से तीन सौ ट्रैक्टर रेत का परिवहन किया जा रहा था ।जिससे नदी का सीना छलनी हो रहा था ।वहीं नदी अपना स्वरुप बदल रही थी ।इस क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा का भरमार होने के कारण रेत माफिया इसका पूरा फायदा उठा रहा है ।जिससे नदियों और पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

खुद को मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताकर सरपंच को किया ब्लैकमेल

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के केरा गांव के सरपंच लोकेश कुमार शुक्ला को फोन कर खुद को मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताकर ब्लैकमेल करते हुए पैसे की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ग्राम खोरयान्ना थाना केटरा झांसी से गिरफ्तार किया है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी अनुसार, नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के केरा गांव के सरपंच लोकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि 2 जुलाई को फोन आया जिसमें आरोपी ने कहा कि मैं मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बोल रहा हूं और तुम्हारे खिलाफ टोल फ्री नबर से 10 से 20 लोगों ने भ्रष्टाचार करने की शिकायत दर्ज कराई है। जिस पर रायपुर से जांच टीम जाएगी, अगर उन्हें गड़बड़ी मिली तो 10 से 20 लाख रु की रिकवरी भरना पड़ेगा, साथ ही आपकी सरपंची भी जाएगी। वह धमकाते हुए बोला कि आज रविवार है सब अधिकारी मंत्रालय में सीसीटीवी कैमरा बंद कर बैठे हैं, चाय पानी के लिए कुछ खर्चा करो सभी अधिकारियों ने पार्टी करने की बात कही और फोन पे पर पैसे को भेजने कहा, जब फोन पे नंबर मांगने पर फोन काट दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएपी विजय अग्रवाल ने विशेष टीम और सायबर सेल की टीम को मोबाइल धारक आरोपी को खोजबीन के लगाया गया। इस दौरान सायबर टीम को मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश टीम भेजी गई। जहां आरोपी पुस्पेंद्र कुमार यादव उम्र 28 साल। निवासी खोरयान्ना थाना कटेरा झांसी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध धारा 384,419,506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

टमाटर की फसल को हाथियों ने रौंदा, घरों को पहुंचाया नुकसान

जशपुर। पत्थलगांव क्षेत्र में हाथियों ने किसानों की टमाटर सहित अन्य फसलों को रौंदने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। वन कर्मचारियों के दल ने आज बीती रात को रेड़े गांव का रिहायशी इलाके से दो हाथियों को खदेड़ कर एक घर से दो बुजुर्ग लोगों को निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, ये लोग बाल बाल बच गए। दो दिन से इन हाथियों ने पत्थलगांव का पेमला, रेड़े और सरईटोला गांव में पहुंच कर बार बार उत्पात मचाया है। हाथियों ने किसानों के खेतों में सागसब्जी की फसल तथा घरों को रौंद कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया है। इस के साथ यंहां रखे अनाज को भी सफाचट कर डाला। आज सुबह ये हाथी पेमला स्कूल के समीप विचरण कर रहे थे। इसके बाद वन कर्मियों ने आसपास के 3 गांव में अलर्ट रहने को कहा है। कल यंहा हाथियों के विचरण के बाद स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। वन विभाग के कर्मचारी लगातार इन हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख कर पहले से ही सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं।

पत्रकारों से दुर्व्यवहार की एनएसयूआई ने की निंदा

धमतरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा परीक्षा परिणाम में धांधली होने की मांग को लेकर शहर के अंबेडकर चौक में चक्का जाम किया गया जिससे आवागमन काफी समय तक बाधित रहा। इस चक्का जाम में एबीवीपी कार्यकर्ताओ सहित भाजपा और भाजयुमो के नेता भी पहुंचे थे, साथ पत्रकारगण मामले को कवरेज करने पहुंचे थे, जिनके सवालों पर भाजयुमो के एक नेता पत्रकारों से उलझ गए और उनसे बहस करने लग गए, भाजयुमो नेता द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि भाजपा अपने नेता सांसद बृजभूषण के पद चिन्हों पर चल रहा है अभी कुछ दिनों पहले ही बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पत्रकार से बदसलूकी की और आज भाजयुमो के पदाधिकारी पत्रकारों से उलझते नजर आए! एबीवीपी केवल छात्रों को बरगलाने का काम करती है ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भाजपा दबाने का काम करती है।

डीजल चोरों का बढ़ा आतंक खदान बंद कराने की धमकी

कोरबा। कुसमुंडा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों ने खदान परिसर में क्यूआरटी के माध्यम से डीजल चोरी को पकड़ने के लिए दबिश दी। जवानों ने बरकुटा फेस में एक टैंकर डीजल चोरी करते देखा। जवानों ने उसका पीछा किया, लेकिन टैंकर चालक मौके से टैंकर सहित वहां से भाग निकला। एसईसीएल के अधिकारियों ने बताया कि चोरों ने विभागीय सुरक्षा जवानों से गाली-गलौज करते हुए खदान बंद करने की धमकी दी है। एसईसीएल प्रबंधन ने पत्राचार कर थाना प्रभारी को टैंकर मालिक और ट्रांसपोटिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधी शिकायत की है। शिकायत पर थाना प्रभारी थाना कुसमुंडा को प्राप्त रिपोर्ट पर टैंकर वाहन को जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद पता चला कि टैंकर का मालिक अभिषेक आनंद है। अभिषेक केडी ट्रांसपोर्ट में बतौर मुंशी है।

भाजपा ने नौ सूत्रीय मांगो को लेकर किया विरोध प्रर्दशन

कोरबा। कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। गुरूवार को कटघोरा विधायक पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए हरदीबाजार बस स्टैंड में नौ सूत्रीय मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ देखी गइ। जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया उसमें एसईसीएल से प्रभावित किसानों के लंबित मुआवजा का भुगतान एवं नौकरी। स्थानीय बेरोजगोरों को एसइसीएल के नियोजित कंपनियों में प्राथमिकता के साथ रोजगार दिलाने की मांग शामिल रहा। अन्य मांगों में कोल माइंस क्षेत्र में कोयला व डीजल चोरी एवं कमीशन खोरी पर रोक, बिजली की अघोषित कटौती व मनमाने बिजली बिल भेजने पर रोक, कटघोरा को जिला बनाने, दीपका से हरदीबाजार मार्ग का नवीनीकरण की मांग पर विभिन्न वक्ताओं ने जोर दिया। सिरकी मोड़ से तिवरता के आउटर तक रोजाना लगने वाले जाम व हरदीबाजार कालेज चौक में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की गई।

छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा, जिला स्वीप नोडल सीईओ जिला पंचायत श्री विश्वदीप के निर्देशन में और उप निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खांडे के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजगामार में 17 से अधिक उम्र के बच्चों, उपस्थित पालको एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को मताधिकार और मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा रजगामार कॉलोनी में क्रमबद्ध रैली निकालकर जागरूक एवं अच्छे मतदाता बनने के लिए अपनी भागीदारी अवश्य निभाने की अपील की गई। मतदाताओं से संकल्प के रूप में 'छोड़ो अपने सारे काम पहले चलो करें मतदान' यह भी नारा लगवाया गया। सभी ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में जिला स्वीप उप नोडल अधिकारी अनिल रात्रे ने उपस्थित मतदाताओं को अन्य मतदाताओं को भी जागरूक करते हुए सभी को मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान करने प्रेरित किया।

विधानसभा में गूंजी कोलियारी-खरेंगा मार्ग की मांग की आवाज

विधायक रंजना साहू ने लगभग हर सत्र में इस विषय को गंभीरता से सदन में रखा

■ **जर्जर सड़क, अवैध माइनिंग, ओवरलोडेड हाईवा गाड़ियाँ बन रही लोगों के जान की दुश्मन**

धमतरी। सड़क से लेकर सदन की लड़ाई जिस मांग को लेकर क्षेत्रवासी लड़ रहे हैं, उस मांग को पुनः विधानसभा के पटल पर विधायक रंजना साहू ने रखकर सदन को अवगत कराया। यह बात हो रही है क्षेत्र की सबसे बहूप्रतीक्षित मांग कोलियारी दर्री खरेंगा दोनर मार्ग सड़क निर्माण चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की, जिसके लिए विधायक रंजना साहू ने पदयात्रा किए और निरंतर सड़क निर्माण की मांग सदन पर उठाई, इसके साथ साथ क्षेत्र के सभी ग्रामीणों ने संघर्ष समिति का निर्माण कर इस मार्ग को निर्माण कराने के

लिए धरने पर बैठे यहां तक की सड़क संघर्ष समिति के द्वारा पदयात्रा निकाली गई किंतु आज पर्यंत तक कागजी फाइलों में स्वीकृति के नाम से ढिंढोरा पीटा जाता रहा, कुछ दिन पूर्व ही इस मार्ग के दोनर ग्राम के पास एक शिक्षक की मृत्यु हुई जिस पर पुनः भाजपाइयों के द्वारा चक्का जाम करते हुए धरना दिया गया, सड़क संघर्ष समिति के द्वारा पदयात्रा भी निकाली गई किंतु इस पदयात्रा को कुछ दूर पर ही रोक दिया गया, खनिज विभाग की लापरवाही और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह रोड जर्जर स्थिति में है और दुर्घटनाओं के कारण अनेक लोगों की जाने चली गई है। विधायक रंजना साहू ने विधानसभा के सदन पर शुन्यकाल के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराया की 10 जून से जो खदानें बंद हो जानी चाहिए थी वह आज भी संचालित है और निरंतर खनिज का दोहन किया जा रहा है जिसके कारण रोड अत्यंत जर्जर स्थिति में है और एक शिक्षक की मौत रेत से भरे हाईवा के कुचलने से हो गई। रोड निर्माण के नवीनीकरण संधारण के लिए राशि स्वीकृति की गई थी किंतु अधिकारियों के उदासीनता के कारण टेंडर प्रक्रिया वर्तमान परिस्थिति में अपूर्ण है। इन सभी घटनाओं का दोषी शासन-प्रशासन की उदासीनता है। ज्ञात हो कि इससे पहले विधायक रंजना साहू के द्वारा कोलियारी दर्री खरेंगा दोनर मार्ग को एडीबी में योजना में शामिल कराया गया किंतु लेटलतीफी के कारण पुनः इस मांग को विधानसभा पटल पर बजट सत्र में रखी जिसको बजट में शामिल किया गया।

विधायक द्वारा सदन में उपस्थापित करने धमतरी के दस महत्वपूर्ण विकास कार्यों की याचिका को मिली स्वीकृति

धमतरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। यह सत्र इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है जो की कई मायनों में सभी सदस्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धमतरी विधायक रंजना डिपेंद्र साहू भी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर काफी गंभीर और मुखर रहती हैं। इस सत्र में भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के काफी महत्वपूर्ण विषय सदन में रखने की याचिका उपस्थापित की जिसमें दस प्रमुख मांगों की याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति उन्हें प्रदान की गई,जिसमें श्रीमती साहू धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण,रुद्री गंगरेल मार्ग के चौड़ीकरण,शासकीय कन्या महाविद्यालय तक स्ट्रीट लाइट एवं पुलिया निर्माण करने,ग्राम संबलपुर से परेवाडीह मार्ग का डामरीकरण, ग्राम रुद्री से बरारी मार्ग डामरीकरण, ग्राम छाती से झुरानवागांव मतंग का डामरीकरण, ग्राम उड़ेना से झिरिया मार्ग में पुलिया निर्माण करने, भटगांव में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के स्टेनो हिंदी एवं डीज़ल मेकेनिक ट्रेड प्रारंभ करने, नगर पंचायत आमदी के हायर सेकंडरी स्कूल में अहाता निर्माण करने, ग्राम सेमरा एवं देवरी नाले पर स्टापडेम निर्माण करने एवं नगर पंचायत आमदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी,वहीं इनसब के अलावा विधायक ने कोलियारी दर्री खरेंगा मार्ग की भी आवाज़ सदन में बुलंद की,विदित हो विधायक श्रीमती साहू पहली बार विधायक बन कर सदन में पहुंची है उसके बावजूद वो बेहद सक्रिय हैं क्षेत्र के विकास को लेकर काफी सजग हैं और बहुत ही गंभीरता से सदन में अपनी बात रखती हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

मेरा काम राज्य में शांति लाना हम किसी को नहीं बख्शेंगे

इंफाल। पिछले 2 महीनों से हिंसा की चपेट में रहे मणिपुर का एक वीडियो वायरल होने के बाद से बवाल और बढ़ गया है। इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। हालांकि, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन विपक्षी लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों की ओर से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। हालांकि एन बीरेन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा काम राज्य में शांति स्थापित करना है और मैं इस काम को कर रहा हूं। किसी भी उपद्रवी तत्व को हम नहीं छोड़ेंगे। आज अपने बयान में एन बीरेन सिंह ने कहा कि घटना को लेकर राज्य भर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर एक, जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था, कल उसका घर महिलाओं ने जला दिया था। उन्होंने कहा कि मणिपुर का समाज महिलाओं के खिलाफ अपराध के खिलाफ है।

चिदंबरम ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का किया अनुरोध

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को भाजपा गठबंधन के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन वांछनीय है और हिंसा को रोकने के लिए मैती और कुकी समुदायों को सक्षम करने के लिए एक तटस्थ प्रशासन का आग्रह किया। ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा, मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागाओं को सभी द्वारा स्वीकृत कानूनी व्यवस्थाओं के तहत एक साथ रहना पड़ता है। प्रत्येक जातीय समूह को दूसरे समूह से शिकायतें होती हैं। भले ही कौन सही या गलत है, अंततः तीनों समूहों को प्रत्येक आदेश से बात करनी चाहिए और एक सामाजिक और राजनीतिक समझौते पर पहुंचना चाहिए। चिदंबरम ने यह भी कहा कि हिंसा के कारण सभी पक्षों ने बहुमूल्य जान गंवाई है और सभी पक्षों को नुकसान हुआ है, इसलिए सभी वर्गों को दोषारोपण बंद करना चाहिए और हिंसा को रोकने का संकल्प लेना चाहिए।

भाजपा ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार

नई दिल्ली। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही विपक्ष केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में देश की महिलाएं आपको देश की राजनीति से बाहर कर देंगी। ममता के बयानों पर बीजेपी ने तुरंत ही पलटवार भी किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान बीजेपी की महिला सदस्य को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप लगाया। सुकांत मजूमदार ने कहा, मणिपुर में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के दक्षिण पांचला में भाजपा की महिला सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या ये मणिपुर से कम दु:खद घटना है?

एनसीटी संशोधन विधेयक पर वोटिंग से बसपा ने बनाई दूरी

नईदिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) संशोधन विधेयक पर चर्चा के साथ-साथ मतदान से भी दूर रहने का फैसला किया। यह कदम महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को राज्यसभा में संख्या जुटाने में कठिनाई हो रही है। पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में विधेयक की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो बसपा मतदान से भी दूर रहेगी। जहां लोकसभा में बसपा के नौ सदस्य हैं, वहीं उच्च सदन में उसका केवल एक सांसद है। विपक्ष को आश्चर्यचकित करते हुए, तेलंगाना स्थित भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) - जो विपक्ष के एकता मंच का हिस्सा नहीं थी। गुरुवार को सदन के आधिकारिक कामकाज में विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक को शामिल करने के विरोध में राज्यसभा की व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक से अन्य विपक्षी सांसदों के साथ बहिर्गमन कर गई थी।

नीतीश पर हमला करते हुए सुशील मोदी ने पूछे कई सवाल

पटना। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से उन पर प्रहार किया है। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर पूछा है कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि क्या केंद्र में उनकी सरकार आने के बाद धारा 370 को फिर से बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष दिल्ली में ऐसी सरकार चाहता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक न कर सके? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तो धारा-370, सर्जिकल स्ट्राइक, नोट बंदी और जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था। अब क्या वे अपने फैसले को गलत मानते हैं? मोदी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार किसान सम्मान निधि की शुरुआत, फौरी तीन तलाक पर रोक और सामान्य वर्ग के युवाओं को 10 फीसद आरक्षण (ईडब्लूएस कोटा) जैसे ऐतिहासिक फैसले भी बदल देना चाहते हैं?

मणिपुर-दिल्ली अध्यादेश पर संसद में महासंग्राम

दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र के शुक्रवार को दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11.00 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा तेज हो गया। दिल्ली में सेवा मामले पर अध्यादेश कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार द्वारा उसके स्थान पर विधेयक लाए जाने का विरोध हुआ। विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की भी कार्यवाही मणिपुर मामले को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामला उठा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर की घटना पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष गंभीर नहीं दिखाई पड़ता है। लोकसभा में मणिपुर के विषय पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार का पक्ष रखते हुए सदन के उप नेता सिंह ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के विषय पर चर्चा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं कहा है कि इससे पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि नारे लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि यह चर्चा और संवाद से ही होगा। उन्होंने कहा, "यह अच्छी बात नहीं है। समाधान केवल चर्चा से ही हो सकता है।" सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में अपनी मांग उठाने लगे। कांग्रेस, द्रमुक और वामदलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रस्ताव पर फिलहाल आम-सहमति नहीं बनी है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार पूछे गये थे।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ

संसद सत्र की ओर देखती है और यह विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते तो अपने आप में ही इनकी भूमिका पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। हम संवेदनशील हैं और चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भाग रहा है और चर्चा से भी भाग रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुरुवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में जो हुआ है उससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। यह एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिससे राज्य गुजर रहा है, सभी समुदाय पीड़ित हैं। अपराधियों को पकड़ना होगा, कल कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और मुझे यकीन है कि बाकी लोगों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आपका (विपक्ष) चर्चा ना करना ये दर्शाता है कि आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है। आप हल चाहते ही नहीं हैं। आप बातों को स्पीकर के पास जाकर चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं। आप चाहें तो आज चर्चा शुरू हो जाएगी, सत्ता पक्ष भी मामले को सुलझाना चाहता है, वे भी चाहता है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर के बारे में सदन के बाहर बयान दिया, जबकि उन्हें सदन के अंदर पहले बयान देना था फिर बाहर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बाहर बयान दे दिया। जब सदन चल रहा है तो सभी नेता अपने सदस्यों को पहले बयान दे फिर बाहर दे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी होती है। पीएम मोदी ने इस पर अपनी विफलता दिखाई। मणिपुर के सीएम को बर्खास्त जरूर करना चाहिए।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर की घटना की चर्चा देश और दुनिया के हर कोने में हो रहा है, इसलिए हमने पीएम मोदी और सत्तारूढ़ पार्टी से सदन में इस घटना पर चर्चा करने का अनुरोध किया था, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि सदन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने इस घटना पर सदन के बाहर बयान दिया। ये सदन के अंदर बोलते तो हैं कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सदन के अंदर क्या बोलना चाहते हैं वे हमें ये मौका नहीं देते हैं।

इस बीच, आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज राज्यसभा में हम सभी ने मिलकर अध्यादेश का मुद्दा उठाया। हमने ये बात उठाई है कि ये काले अध्यादेश हैं और इसे वापस लेना चाहिए। ये सदन में ना पेश होने चाहिए और ना ही इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। हमें विश्वास है कि राज्यसभा के अध्यक्ष हमारी बात को स्वीकार करेंगे और इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार को सलाह देंगे। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर जल रहा है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को उनके 81वें जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि उनके विवेक व हास-परिहास का अंदाज सताते हुए मौसम को भी बदल देता है। मणिपुर हिंसा, दिल्ली के सेवा मामले पर अध्यादेश के अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार द्वारा उसके स्थान पर विधेयक लाए जाने और सदन की कार्यवाही से कुछ अंशों को हटा देने के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ढाई बजे जैसे ही दोबारा सदन की बैठक शुरु हुई सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के उपराज्यपाल को शक्तियां प्रदान करने के प्रावधान वाले 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक' का जिक्र किया। इसी समय संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने इसका विरोध किया और इस कदम को 'गैर संवैधानिक' बताया। कार्यवाही आरंभ होने के एक मिनट के भीतर ही धनखड़ ने सदन की बैठक सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज

मप्र में ऐसी सरकार बनाए जो खरीदी न जा सके : प्रियंका

ग्वालियर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंची। प्रियंका ने जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत और अंत बुंदेलखंडी में किया। अपने 32 मिनट के भाषण में प्रियंका ने केवल एक बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। प्रियंका ने भाषण में सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया और क्यों किया। इन सब में अब जाने की जरूरत नहीं है। आज केवल मुद्दों की बात करने आपके बीच आई हूं। आज लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। आज इन मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान की जरूरत है। प्रियंका ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने रैली में वहीं पांच गारंटी को फिर दोहराया, जिनकी घोषणा उन्होंने जबलपुर रैली में की थी। साथ ही यह भी कहा कि प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार बनाए जो न खरीदी जा सके, न गिराई जा सके। जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए।

प्रियंका ने अपना संबोधन बुंदेलखंडी में संबोधन शुरू किया। कहा- सब भैया-बहन आपको हमारी राम-राम। हमारे देश की परंपरा रही है कि हम नेताओं में सरलता, सभ्यता और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नेता में ऐसे गुण हों। आरोप-प्रत्यारोप, एक-दूसरे की बुराई के बीच जनता के असली मुद्दे डूब जाते हैं। मैं आज पीएम, शिवराज और सिंधिया के बारे में 10-10 मिनट बोली सकती हूं। सिंधिया जी के बारे में भी 10 मिनट बोल सकती हूं, कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन मैं आज आप लोगों का ध्यान भटकाने नहीं आई हूं। मैं आज आम लोगों के मुद्दों

पर बात करने आई हूं। मैं महंगाई के मुद्दों पर बात करने आई हूं। आज हर तरफ महंगाई है। ये आपके जीवन पर एक बोझ बन गई है। किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। सबसे ज्यादा महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठा रही हैं। गैस सिलेंडर हजार रुपये से कम में नहीं मिल रहा। कोई बीमार पड़ा जाता है तो इस बात की घबराहट होती है कि दवा कहां से लेकर लाए। इस बीच मुझे उचित नहीं लगता है कि मैं दूसरों की आलोचना करती रहूं।

प्रियंका ने वादे करते हुए कहा कि हमारी जहां-जहां सरकारें हैं, वहां जो गारंटी दी वो निभाई जा रही हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, तो सरकार कहती है, पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में आज पेंशन सुविधा है। छत्तीसगढ़ में 2600 रुपये आपको धान के लिए मिलते हैं। कर्नाटक में हमने कहा था- बस में महिलाएं फ्री यात्रा करेंगी। अब ये सेवा भी शुरू होने जा रही है। आज मप्र में भी बदलाव की लहर है। प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो न खरीदी जा सके, न गिराई जा सके। जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि, यहां से तमाम वीर जाकर देश की सेवा करते हैं। जब से अग्निवीर योजना आई, तब से लोग ट्रेनिंग से ही वापस आ जा रहे हैं। घर आकर किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

विराट टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 500 मैच पूरे कर लिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में राष्ट्रगान के लिए मैदान पर कदम रखते ही कोहली ने भारत के लिए अपने 500 मैच पूरे कर लिए। इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस मैच में पहले दिन ही विराट बल्लेबाजी के लिए आए और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल कई और रिकॉर्ड बनाए। विराट कोहली दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच टेस्ट फॉर्मेट में खेला है। उनसे पहले नौ खिलाड़ियों ने 500 या इससे ज्यादा मैच खेले, लेकिन सभी का 500वां मैच वनडे या टी20 फॉर्मेट में रहा। इसी वजह से विराट से पहले कोई भी खिलाड़ी अपने 500वें मैच में अर्धशतक तक नहीं लगा सका था। वहीं, कोहली 500वें मैच की पहली पारी में ही शानदार अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं और उनके पास शतक पूरा कर एक और उपलब्धि अपने नाम करने का बेहतरीन मौका है। विराट कोहली 500वें मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। अब तक जितने खिलाड़ियों ने 500 या उससे ज्यादा मैच खेले हैं, उनमें कोई भी गेंदबाज नहीं है। हालांकि, शाहिद अफरीदी, सनथ जयसूर्या और जैक्स कैलिस जैसे ऑलराउंडर जरूर इस सूची में हैं, लेकिन कोई भी विशुद्ध गेंदबाज अब तक 500 मैच नहीं खेल पाया है। सचिन तेंदुलकर 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 2006 में यह उपलब्धि हासिल की थी। उनके बाद 2007 में सनथ जयसूर्या, 2010 में रिकी पोंटिंग, 2011 में राहुल द्रविड़ और महेला जयवर्धने ने यह उपलब्धि हासिल की। 2012 में जैक्स कैलिस, 2013 में कुमार संगाकारा, 2015 में शाहिद अफरीदी और 2018 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 500वां मैच खेला।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में 888 अंक टूटा निफ्टी 19,750 के करीब

नईदिल्ली। पिछले कुछ सत्रों से शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को निफ्टी 50 के 20 हजारी होने की उम्मीद की जा रही थी। मगर आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के पहली तिमाही24 कमजोर नतीजों और वृद्धि पूर्वानुमान में कमी ने प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सेंसेक्स करीब 888 अंक लुढ़क गया। वहीं निफ्टी में भी 230 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। बाजार की ब्लूचिप कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में गिरावट से भी कारोबारियों की धारणा प्रभावित हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 887.64 अंक यानी 1.31 फीसदी की गिरावट के साथ 66,684.26 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 67,190.52 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 66,533.74 तक आया।

36.5 फीसदी गिरा वेदांता ग्रुप की कंपनी का नेट प्रॉफिट

नईदिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए अपने शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 36.48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। इसके साथ कंपनी के मुनाफे में 1,964 करोड़ रुपये की कमी आई। बता दें कि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 3,092 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी के मुनाफे में कमी आने की मुख्य वजह कम इनकम बताई जा रही है। अप्रैल-जून की इस अवधि में समेकित कुल आय भी एक साल पहले की अवधि में 9,697 करोड़ रुपये के मुकाबले गिरकर 7,564 करोड़ रुपये हो गई। पहली तिमाही 23 की तुलना में कंपनी के परिचालन राजस्व में भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

स्टील की दिग्गज कंपनी जिंदल को हुआ 189 फीसदी मुनाफा

नईदिल्ली। स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने शुक्रवार को बताया कि 30 जून,2023 को समाप्त हुई तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 189.3 प्रतिशत बढ़कर 2,428 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 839 करोड़ रुपये था। इस अवधि के दौरान कंपनी का परिचालन से राजस्व पिछले साल के 38,086 करोड़ रुपये के मुकाबले 10.3 प्रतिशत बढ़कर 42,213 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 31 मार्च को खत्म हुई पिछली तिमाही के 3,741 करोड़ रुपये से कम रहा। इससे पहले कंपनी के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा था कि कंपनी अगले तीन साल में अपनी क्षमता लगभग दोगुनी कर 50 मिलियन टन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी पूरे 50 मिलियन टन उत्पादन को चालू करने के लिए बिजली के रिन्यूबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होने का भी लक्ष्य बना रही है।

वाहन कंपनी अशोक लीलैंड का 747% नेट प्रॉफिट बढ़ा

नईदिल्ली। हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व वाली वाहन कंपनी अशोक लीलैंड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 747 प्रतिशत बढ़कर 576.42 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने शुक्रवार को बीएसई फाइलिंग में जानकारी दी। जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 66.05 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। पहली तिमाही 24 के लिए परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 13.3 फीसदी बढ़कर 8,189.29 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की तिमाही में राजस्व 7,222.65 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ क्योंकि कामकाजी मुनाफा (एबिटा) पहली तिमाही 24 में बढ़कर 820.8 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 320.2 करोड़ रुपये थी।

भारत की ओर रुख करते विदेशी निवेशकों की वजह से चीन परेशान

सतीश सिंह

मौजूदा समय में अमेरिका सहित लगभग तमाम विकसित देशों के शेयर बाजार में बिकवाली का दौर जारी है। उतार-चढ़ाव के साथ-साथ वहां शेयर बाजार तेज गोते भी लगा रहा है। कोरोना महामारी, भू-राजनैतिक संकट, रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत की वजह से विकसित देशों में शेयर बाजार की हालात खस्ता है। इतना ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी देखी जा रही है और कुछ देशों में मंदी के आसार बने हुए हैं।

इसके ठीक उलट भारतीय शेयर बाजार में विगत कुछ महीनों से उछाल की स्थिति बनी हुई है। शेयर बाजार की सेहत का हाल बताने वाले 30 प्रतिनिधि शेयरों का संवेदी सूचकांक तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। एक साल पहले जहां यह 55,000 के पास था, वहीं अब यह 67,000 के ऊपर जा चुका है। सेंसेक्स ने तीन जुलाई को 65,000, 14 जुलाई को 66,000 और 19 जुलाई को 67,000 का स्तर पार किया था। शेयर बाजार की विगत महीनों की प्रवृति को देखने से लगता है कि इस साल के अंत तक बीएसइ संवेदी सूचकांक 70,000 के स्तर को पार कर सकता है।

ऐसी ही कुछ हालत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ) के 50 प्रतिनिधि शेयरों के सूचकांक निफ्टी-50 की है। पिछले साल जुलाई में यह 16,500 के आस-पास था और अब यह बढ़कर 20,000 के निकट पहुंच गया है। मौजूदा परिदृश्य में निफ्टी इस साल के अंत तक 21,000 के स्तर पर पहुंच सकता है। शेयर बाजार में लगातार उछाल की स्थिति बने रहने की वजह से पिछले 3 महीनों में निवेशकों की संपत्ति में 40 लाख करोड़ रुपये

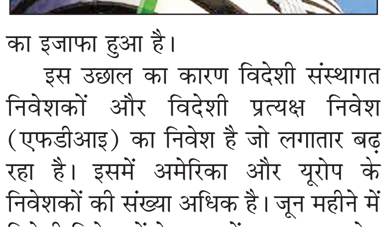

का इजाफा हुआ है।

इस उछाल का कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) का निवेश है जो लगातार बढ़ रहा है। इसमें अमेरिका और यूरोप के निवेशकों की संख्या अधिक है। जून महीने में विदेशी निवेशकों ने भारत में 47 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया था।

भारत की ओर रुख करते विदेशी निवेशकों की वजह से चीन की परेशानी बढ़ रही है। विदेशी निवेशक चीन के शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। दरअसल, चीन के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में गिरावट और निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती से निवेशकों का चीन की अर्थव्यवस्था में भरोसा कमजोर हुआ है। चीन में इस साल के पहले दो महीने में विदेशी निवेशकों ने अच्छा-खासा निवेश किया था, लेकिन बाद के महीनों में उन्होंने 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की निकासी की।

फिलहाल विदेशी निवेशक चीन की जगह भारत में निवेश करना बेहतर मान रहे हैं। वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार तीन ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर पांच ट्रिलियन डॉलर तक हो जाने की बात कही जा रही है। एचएसबीसी की हालिया रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले पांच से 10 सालों में सात ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से सुस्त हो गयी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुधार का दौर जारी है। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में बेहतरी आने से पूरे वित्त वर्ष की वृद्धि दर में में 7.2 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया गया है।

शेयर बाजार में बांड, म्युचुअल फंड और डेरिवेटिव भी खरीदे एवं बेचे जाते हैं। किसी कंपनी के कामकाज का मूल्यांकन ऑर्डर मिलने या नहीं मिलने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने, आयात या निर्यात होने या नहीं होने, कारखाने या फैक्ट्री में कामकाज ठप्प पड़ने, उत्पादन घटने या बढ़ने, तैयार माल का विपणन नहीं होने आदि जानकारियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए, कंपनी पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव के आधार पर शेयरों की कीमत में रोज उतार-चढ़ाव आता है। आमतौर पर ज्यादा प्रतिफल मिलने की आस में घरेलू एवं विदेशी निवेशक, शेयर के रूप में कंपनियों में निवेश करते हैं।

26 बनाम 38 की जोर आजमाइश का सत्र

अनिल तिवारी

नवनिर्मित संसद भवन की बजाय पुराने संसद भवन में ही आज से संसद का मानसून सत्र शुरु हो गया है। इस बार संसद के मानसून सत्र में प्रेस, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डाक सेवा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, संविधान संशोधन, जैविक विविधता सहित कुल 32 विधेयकों पर विचार किया जाना है। हालांकि बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, जन विश्वास विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विषयक अध्यादेश को लेकर सदन के भीतर गर्मी बढ़ने की संभावना है लेकिन बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के कारण उसके पेश होने की संभावना कम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सत्र में अभी-अभी बंगलुरु में यूपीए से बदल कर इंडिया बना विपक्ष जोर शोर से अपनी एकजुटता की मुहिम का राजनीतिक प्रदर्शन करना चाहेगा तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष, विपक्षी खेमे की कोशिशों को सदन के भीतर ही हराकर उसके पेच ढीले करने की कोशिश करेगा। मालूम हो कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। सत्र में कुल 32 अहम विधेयक पारित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें उस अध्यादेश को भी कानूनी रूप दिया जाएगा जिसका प्रयोग करके दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौकरशाहों पर मिले अधिकार को खत्म कर दिया गया था। कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे पर केजरीवाल का साथ देने की बात कह चुकी है, इसलिए जिस दिन यह विधेयक संसद में आयेगा, हंगामा होना तय है। पिछले सत्र का अनुभव कड़वा रहा है। अडानी के मामले पर विपक्ष ने संसद के कामकाज में लगातार अड़ंगा लगाया। संसद ने सभी वर्गों के हित में कानून बनाने की अपनी बुनियादी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई। किसी ना किसी बहाने सांसदों ने काम कम कोहराम ज्यादा मचाया। तर्कसंगत विरोध, असहमति और फिर आम राय से किसी नतीजे पर पहुंचने की अवधारणा गंभीर रूप से घायल हुई। पिछले सत्र में सभापति जगदीप धनखड़ ने कई बार याद दिलाया कि संसद किसलिए और किसके खातिर बनी है? इस पर सांसदों को गौर करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि सदन के अंदर ऐसे हंगामे को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक हलचलों को देखते हुए लगता है कि मानसून सत्र में भी संसद में काम कम बातें अधिक होंगी। सत्र के दौरान दिल्ली प्रशासन से जुड़े अध्यादेश का ऐसा मुद्दा आना है जिसमें विपक्षी दलों को अपनी एकजुटता दिखाने का मौका मिलेगा। विपक्ष की रणनीति होगी कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को राज्यसभा में परास्त कर आम चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जाए। इसके अतिरिक्त मणिपुर की हिंसा और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के मामले पर हंगामे के आसार हैं। महंगाई के बहाने विपक्ष आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार को घेरने की घोषणा कर चुका है। बेरोजगारी का मसला भी विपक्ष जोर शोर से उठाना चाहता है। मानसून सत्र में सदन के भीतर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट होगी। इंडिया के सहयोगी दलों के सुर ताल की भी जांच हो जाएगी। वहीं, जिन पांच बड़े राजनीतिक दलों ने किसी भी गठबंधन में शामिल ना होकर अपना अलग वजूद बनाए रखने का दम भरा है, सदन के भीतर उनके तेवर कैसे हैं, इसका भी अंदाजा मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी भी सूरत में मानसून सत्र में अपनी पकड़ कम नहीं होने देने के साथ-साथ अहम बिलों को पास कराने की योजना तैयार की है। सरकार इसके लिए अन्य दलों से संवाद स्थापित करने और मौका मिलने पर विपक्षी दलों में सेंध लगाने का भी प्रयास कर सकती है। सरकार को भरोसा है कि बीजू जनता दल और वाईएसआर जैसे राजनीतिक दल विपक्ष के खेमे में नहीं जाएंगे। भारतीय जनता

संसद से बड़ा दिखना चाहता है सुप्रीमकोर्ट?

अजय सेतिया

1991 में संविधान में उनसठवां संशोधन करके अनुच्छेद 239 में 239एए जोड़ा गया था। यह संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक विधानसभा देने के लिए था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, केंद्र शासित राज्य कहा गया था और अनुच्छेद 239एए (3) में कहा गया है कि इस संदर्भ में संसद कभी भी कोई भी कानून बना सकती है। संसद को विधान सभा के बनाए कानून में कुछ जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार भी होगा। 239एए (7) में भी कहा गया है संसद क़ानून के माध्यम से मौजूदा प्रावधानों में कोई प्रावधान जोड़ सकती है। केंद्र सरकार ने इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत 20 मई को एक अध्यादेश जारी किया, इस अध्यादेश का मूल मुद्दा यह था कि दिल्ली में नियुक्त दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। दानिक्स में दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेस आते हैं।

केंद्र सरकार ने संविधान में मिले अधिकार के अंतर्गत ही क़ानून में संशोधन किया है, लेकिन दिली सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी कि यह सुप्रीमकोर्ट के फैसले को बदलने के लिए लाया गया अध्यादेश है। सुप्रीमकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इसे संविधान में संशोधन मान कर पांच सदस्यीय पीठ को सौंप दिया है। जिससे केंद्र सरकार और सुप्रीमकोर्ट के बीच एक बार फिर टकराव शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। ऐसी उम्मीद तो केजरीवाल सरकार को भी नहीं रही होगी कि चीफ जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय पीठ अध्यादेश को संविधान संशोधन मान लेगी। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, और एक-आध दिन में सरकार अध्यादेश की जगह पर बिल पेश कर देगी, लेकिन अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि अगर सुप्रीमकोर्ट इसे संविधान संशोधन मान रही है, तो सरकार के सामने मुश्किल खड़ी होगी7 लेकिन सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई कोई एक दिन में तो नहीं जाएगी, इसमें साल भर भी लग सकता है, इसलिए सरकार फिलहाल इसे सामान्य बिल के रूप में पास करवाएगी। जो सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा।

भले ही राज्यसभा में सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं है, फिर भी सरकार को इस बिल के संसद में पास होने में कोई आशंका नहीं है। लोकसभा में तो दो-तिहाई के अंतर से बिल पास होगा, लेकिन राज्यसभा में जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे सरकार ने जुगाड़ कर लेने के बाद ही अध्यादेश जारी किया होगा। राज्यसभा में भाजपा के खुद के 5 मनोनीत सदस्यों समेत 97 सदस्य हैं, और 10 सहयोगी दलों के 13 सदस्य हैं। इस तरह मौजूदा 237 के सदन में एनडीए के 110 सांसद हैं, बिल पास करवाने के लिए उसे सिर्फ 9 अन्य सदस्यों का समर्थन चाहिए। तटस्थ 29 सदस्यों में से भारत राष्ट्र समिति के सात सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी 22 भाजपा के संपर्क में हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजू जनता दल के 9, और टीडीपी, बसपा, जेडीएस और एसडीएफ के एक एक सदस्य अगर बिल के समर्थन में वोट न भी दें, वे तटस्थता बनाए रखने के लिए अनुपस्थित ही हो जाएं, या मतदान में हिस्सा ही न लें, तब भी बिल पास हो जाएगा। इन सभी के मतदान में हिस्सा नहीं लेने से सदन की प्रभावी संख्या 215 रह जाएगी, जबकि एनडीए के अपने सदस्यों की संख्या 110 है, जो सदन में बहुमत के लिए वांछित 108 से 2 ज्यादा है। वैसे किसी भी बिल पर मतदान के समय सौ फीसदी हाजिरी बहुत कम होती है। बिल का प्रारूप अभी सामने नहीं आया है। अध्यादेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिस प्राधिकरण को बनाने की बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि प्राधिकरण को %ग्रुप ए के सभी और दानिक?स के अधिकारियों के तबादलों, नियुक्तियों से जुड़े फैसले लेने का हक़ तो होगा, लेकिन आख़िरी मुहर उपराज्यपाल की होगी। यानी अगर उपराज्यपाल को प्राधिकरण का लिया फैसला ठीक नहीं लगा तो वह उसे बदलाव के लिए वापस लौटा सकते हैं।

फिर भी अगर मतभेद जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश सुप्रीमकोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के कारण जारी किया था। सुप्रीमकोर्ट के 11 मई के फैसले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार ने सुप्रीमकोर्ट का फैसला पलटने के लिए अध्यादेश जारी किया। क्या सरकार को सुप्रीमकोर्ट का फैसला पलटने का अधिकार है? कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, जिसने शाहबानो केस में सुप्रीमकोर्ट का फैसला बदलने के लिए संसद से क़ानून पारित किया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड भी केजरीवाल सरकार से सहमत लगते हैं कि केंद्र सरकार को सुप्रीमकोर्ट का फैसला बदलने का अधिकार नहीं। जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड केशवानंद भारती केस के फैसले को हू-ब-हू लागू करना चाहते हैं कि संसद सर्वोच्च नहीं है, सुप्रीमकोर्ट सर्वोच्च है। सुप्रीमकोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को क़ानून में संशोधन करके तीसरी बार दिए गए सेवा विस्तार को रद्द कर दिया था, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में उनके दूसरे सेवा विस्तार को अंतिम बताया था। पहले के नियम में 60 साल की उम्र में रिटायर होने पर दो साल तक का सेवा विस्तार दिए जाने का प्रावधान था, जिसे सरकार ने संशोधित करके पांच साल कर दिया था।

सुप्रीमकोर्ट ने इसे अपने पूर्व फैसले को बदलने के लिए किया गया संशोधन माना। हालांकि सुप्रीमकोर्ट के जज खुद 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, और उसके बाद भी कई प्राधिकरणों में अगले पांच साल तक मलाईदार पद पाने का कानूनी प्रावधान करवाए हुए हैं। एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि अध्यादेश के मुताबिक़ बनाए गए प्राधिकरण के किसी फैसले पर अगर उपराज्यपाल सहमत नहीं है, तो उसे वह प्राधिकरण को लौटा देंगे, लेकिन प्राधिकरण फिर भी अपने फैसले पर अडा रहता है, तो उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम होगा, प्राधिकरण का नहीं। यह सवाल जायज है, लेकिन यह प्रावधान हू-ब-हू कोलिजियम सिस्टम के प्रावधानों जैसा है, जिसे कोलिजियम ने खुद बनाया है कि उन्हीं का फैसला अंतिम है, सरकार उसे एक बार वापस लौटा सकती है, दूसरी बार नहीं। राष्ट्रपति को उन्हीं के फैसले पर दस्तखत करने पड़ेंगे, भले ही चुनी हुई सरकार उससे सहमत हो या न हो। 11 मई को सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में खुद लिखा था, उनका फैसला किसी क़ानून के अभाव के कारण दिया जा रहा है। 239एए (3) 239 (7) में मिले अधिकार के अलावा इस आधार पर भी केंद्र सरकार को अध्यादेश जारी करके क़ानून बनाने का अधिकार था। कायदे से दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर देनी चाहिए थी।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी को पंगु बनाने और सतर्कता विभाग के अफसरों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार की याचिका खारिज करने की मांग की थी। लेकिन चीफ जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीमकोर्ट की इज्जत का सवाल बना लिया है, इसलिए 17 जुलाई को पहली सुनवाई में उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीमकोर्ट के फैसले को पलट सकती है? हैरानी यह है कि सुप्रीमकोर्ट ने भी 17 जुलाई को सुनवाई के समय कहा कि सरकार ने पहली बार 239एए (3) और 239एए (7) का इस्तेमाल किया है, एक तरफ से यह संविधान में संशोधन किया गया है, सुप्रीमकोर्ट देखेगी क्या सरकार को इसका अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 239एए में जब संसद को क़ानून बनाने का अधिकार पहले से दिया गया है, तो यह संविधान संशोधन कैसे हुआ। चीफ जस्टिस ने अध्यादेश के खिलाफ याचिका को फिर से पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सौंपने का इरादा जता दिया था। सरकार ने संसद में अभी बिल पेश नहीं किया है। लेकिन सुनवाई के दौरान ही याचिका का नेचर बदल जाएगा, क्योंकि तब तक संसद से बिल पास होकर बाकायदा कानून बन चुका होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (अंतिम)

गतांक से आगे...

विश्वस्वरूप देव का जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म या फिर अन्य दूसरे प्रकार का स्वरूप है, जो योगी-साधक उसका अपने कमल रूपी हृदय में ध्यान करता है, वह स्वयं साक्षात् उन्हीं परब्रह्म के स्वरूप का ही हो जाता है। अणिमा लघिमा आदि समस्त सिद्धियों के फल को वह अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् मैं ब्रह्म हूँ इस स्थिति तक पहुँच जाना ही समाधि कही गई है। उसके अन्तर्गत सभी प्रकार की वृत्तियों इच्छाओं का समापन हो जाता है। जो भी योगी मनुष्य इस तरह से परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस नश्वर जगत् में नहीं आता।

इस प्रकार से योगी-साधक योग तत्त्वों का शोधन करता हुआ स्पृहारहित चित्त द्वारा ईंधनरहित अग्नि की भाँति स्वयमेव शान्त हो जाता है। तदनन्तर उस योगी के लिए और कुछ स्वीकार करने योग्य शेष नहीं रहता । उसका मन एवं प्राण सच्चे आत्मज्ञान से सम्पन्न हो जाता है तथा उसकी जीवात्मा शुद्ध पवित्र परमात्म तत्त्व में, जल में नमक की तरह से विलीन हो जाती है।

उस योगी को माया-मोह के जाल में आबद्ध हुआ यह संसार स्वप्न की भाँति दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वह पूर्ण निश्चल होकर स्वभाव वश ही सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। ऐसा श्रेष्ठ योगी-साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर कैवल्यावस्था की स्थिति में पहुँच जाता है, ऐसी ही यह उपनिषद् विद्या है।

विश्व मस्तिष्क दिवस

विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो 22 जुलाई को प्रतिवर्ष होता है। यह पालन पिछले नौ वर्षों से चल रहा है और मस्तिष्क रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में कार्य करता है। इस दिन, विभिन्न स्थानीय और वैश्विक संगठन और समुदाय न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान के लिए अधिक जागरूकता, वकालत और समर्थन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक साथ आते हैं।

इस वैश्विक पहल का उद्देश्य ज्ञान की कमी को दूर करना और मस्तिष्क स्वास्थ्य हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह न्यूरोलॉजिकल विकारों से संबंधित बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान की वकालत करने के अलावा, विकलांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के महत्व पर भी जोर देता है। अतिव्यापी लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी को भी अनदेखा या बाहर नहीं किया जाता है, और यह कि हर किसी को इष्टतम मस्तिष्क स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक समर्थन और ध्यान प्राप्त होता है।

यह दिन आधुनिक युग में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य विभिन्न रोकथाम विधियों को शामिल करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करते हैं और तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं।

इस दिन, पूरी दुनिया भर के विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के लोग आगे बढ़कर मस्तिष्क स्वास्थ्य और इससे संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशालाएं या खुले चर्चे का आयोजन करना, सामाजिक मीडिया पर अपने अनुभवों को साझा करना जिससे मस्तिष्क रोगी व्यक्तियों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है, उनके लिए धनराशि की आवश्यकता होने पर आर्थिक मदद के लिए फंडरेजिंग इवेंट आयोजन करना, मस्तिष्क स्वास्थ्य को सुधारने के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए रैलियों का आयोजन शामिल है।

विश्व मस्तिष्क दिवस की खोज पहली बार विश्व मस्तिष्क दिवस के लिए विश्व न्यूरोलॉजी संघ ने की थी। विश्व न्यूरोलॉजी संघ का खोज 1957 में बेल्जियम में किया गया था और अब यह विश्वभर में मस्तिष्क स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी अनुसंधान के प्रमुख प्रमोटरों में से एक है। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में हर देश के विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। संगठन इसे सशक्त बनाने के लिए सत्यापित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, शिक्षा और अन्य उपाय आयोजित करता है। विश्व न्यूरोलॉजी संघ ने न्यूरोलॉजी अनुसंधान के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए पत्रिकाओं और प्रकाशनों को विस्तारित किया है। इसलिए, विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 विशेषज्ञ संगठन द्वारा उत्पन्न किया गया महत्वपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाने का विचार जन जागरूकता और वकालत समिति द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ। यह प्रस्ताव 22 सितंबर, 2013 को वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी (डब्ल्यूसीएन) काउंसिल ऑफ डेलिगेट्स की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था, और इसे प्रतिनिधियों से गर्म और उत्साही प्रतिक्रिया मिली।इस सकारात्मक स्वागत के बाद, न्यासी बोर्ड ने फरवरी 2014 में आयोजित अपनी बैठक में इस अवधारणा को मंजूरी दे दी, जिससे यह प्रत्येक वर्ष एक ही तारीख को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया।

आजकल बहुत से लोग आमतौर पर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझते हैं, जो चिंता का विषय है। यह आर्टिकल विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 के इतिहास, महत्व, विषय और बहुत कुछ के साथ सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को चित्रित करता है। विश्व मस्तिष्क दिवस हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 पर, कई अग्रणी संगठनों का समर्थन किया जाएगा जो सकारात्मक मस्तिष्क स्वास्थ्य और कुछ संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएंगे। इस मूल्यवान धारणा को प्रदर्शित करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए कई गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी जहाँ लोग अच्छे और स्वस्थ मस्तिष्क के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे।

श्रीलंका और पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश!

कुणाल वर्मा

भारत के तीन प्रमुख पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश विकट आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं। श्रीलंका में पिछले साल जुलाई में जिस तरह आम लोगों ने क्रांति की थी उसने वहां की विषम परिस्थितियों से पूरे विश्व को अवगत कराया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन तक क्रांति की आग पहुंच गई थी। हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा था। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले साल ही दिसंबर महीने में बांग्लादेश भी कुछ ऐसे ही संकटों से घिर गया था।

प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए थे। लगातार बिगड़ रही देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में सरकार को हटाने की मांग को लेकर रैली की थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले साल नवंबर महीने में बांग्लादेश सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से गुहार लगानी पड़ी थी। लगातार आर्थिक संकटों से जूझ रही शेख हसीना सरकार एक बार फिर अपने पैरों पर उठ खड़ा होने की पुरजोर कोशिश में लगी है। यह कोशिश विदेशी ऋण के जरिए अधिक हो रही है। इस क्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चीन से नजदीकियों ने भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है।

एलडीसी रैंक से बाहर निकलने का लक्ष्य

बांग्लादेश का लक्ष्य साल 2031 तक संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकासशील देशों (एलडीसी) की रैंक से निकलकर उच्च-मध्यम आय वाला देश बनना है। हालांकि, हाल ही में आई विश्वबैंक की एक रिपोर्ट ने वास्तविक स्थिति की तरफ ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का वित्तीय क्षेत्र कुछ विकृतियों का सामना कर रहा है, खासकर आर्थिक स्थिरता के रूप में। बांग्लादेश के लिए एक सुकूनदायक बात को भी रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है। विश्व बैंक ने कहा है कि इस आर्थिक संकट को इसके दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, पाकिस्तान और श्रीलंका जितना गंभीर और तत्काल नहीं माना जा सकता है। विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने वाली कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान इस वक्त बांग्लादेश पर है। ऐसा इसलिए है कि छोटा देश होने के बावजूद बांग्लादेश में इतनी क्षमता है कि वो आर्थिक मोर्चे पर बेहतर कर सके। आर्थिक प्रगति और ऋण खर्च का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल 2023 में आईएमएफ ने ढाका का दौरा किया था। इस दौरान आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल ने भी देश में व्याप्त वित्तीय विकृतियों के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। आईएमएफ ने कहा कि बांग्लादेश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बेहतर प्रदर्शन के बावजूद लगातार मुद्रास्फीति दबाव, वैश्विक वित्तीय स्थितियों की बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि प्रमुख उन्नत व्यापार भागीदारों में मंदी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार और बांग्लादेश की मुद्रा टका पर व्यापक असर पड़ रहा है।

कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट का भी असर

बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट ने भी व्यापक असर डाला है। इसके परिणामस्वरूप बिजली और ईंधन की कीमतों में बड़ी वृद्धि हुई है। मई 2023 तक ढाका में मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, बांग्लादेश का भुगतान संतुलन (बीओपी) घाटा भी देश के लिए लगातार आर्थिक चिंता का विषय है। बीओपी घाटा 2022 में 5.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7.2 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके कारण बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार 30 अरब डॉलर से नीचे गिरकर 29.85 अरब डॉलर पर आ गया है।

बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा स्रोत रेमिटेंस (प्रवासियों द्वारा भेजे जाना वाला धन) है। इसमें भी 16.2त्न की गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण चुनौतियां और भी जटिल हो गई हैं। रेडीमेड कपड़ों (आरएमजी) के निर्यात में भी गिरावट ने बांग्लदेश को परेशानी में डाला है। इसमें भी अप्रैल 2023 में 15.4त्न की गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शेख हसीना सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस पर तमाम देशों की नजर है क्योंकि जिस तरह के कदम सरकार उठा रही है वे कई पड़ोसी देशों के लिए आत्मघाती भी साबित हुए हैं। सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है विदेशी ऋण लेने की तरफ। वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में औसत बाहरी उधारी में 3.35 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई है। ढाका ने हाल ही में विश्व बैंक से 2.25 बिलियन डॉलर, आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर और एडीबी से 3.0 बिलियन डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएमएफ, विश्व बैंक और एडीबी जैसे आर्थिक संगठनों के साथ सरकार की भागीदारी को मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट को दूर करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कर्ज लेना एक राजनीतिक रणनीति का संकेत भी देती है। पर इन सबके अलावा कर्ज के मामले में चीन से नजदीकियों ने बांग्लादेश के भविष्य के लिए कई गंभीर प्रश्न भी पैदा किए हैं।

दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे अहम हिस्सा उसका कर्ज जाल (डेब्ट ट्रैप) है। इसके तहत वह गरीब और आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को भारी भरकम कर्ज देकर उन्हें ऐसे मकड़जाल में फंसा देता है जहां से निकलना आसान नहीं। पिछले साल श्रीलंका के मामले में पूरा विश्व यह देख चुका है। श्रीलंका जब कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने उसका हंबनटोटा पोर्ट ही अगले 99 साल के लिए लीज पर रख लिया। पाकिस्तान को भी चीन ने कर्ज के बोझ तले इतना दबा दिया है कि वहां कभी भी कुछ कर सकता है। इसीलिए हाल के दिनों में शेख हसीना से चीन की नजदीकियों के कारण सवाल उठना लाजिमी है।

बापू की दिनचर्या

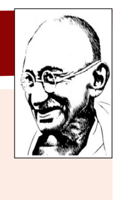

शयन (भाग-2)

गतांक से आगे...

वृद्धावस्था के कारण जाड़े के दिनों में बापू का शरीर और पैर बहुत ठंडे हो जाते। अतः शयन के समय, खून की गति बढ़ाने, ठीक करने या शरीर में गरमी पहुँचाने की दृष्टि से कुछ क्षणों तक वे व्यायाम करते। उनका यह व्यायाम जिमनाजियम के पैरेलल बार की भाँति होता। दो बहनों के कंधों के माध्यम से वे उस क्रिया को करते। रक्तचाप के कष्ट को दूर करने के लिए पहले वे कई प्रकार के यौगिक आसनों का अभ्यास किया करते। कड़ाके की सरदी और बरसात में भी बापू खुले में सोते और बहुत आवश्यकता पड़ने पर रात में कुछ ओढ़ते । दक्षिण अफ्रीका में ऐसा होता, बल्कि उसके पूर्व से वे इसके अभ्यस्त थे। एक बार यरवदा जेल में महादेव भाई से इस विषय पर उनकी चर्चा हुई। उस समय उन्होंने बताया कि अफ्रीका में कड़ी सरदी में ही नहीं, बरसात में भी वे खुले में सोते; किंतु सख्त ठंड में अच्छी तरह ओढ़ने की व्यवस्था रहती। मि. कलनबक काफी कंबल इकट्ठे कर लेते और बरसात के समय ऊपर मोमजामे के कपड़े की तरह कुछ लगा लेते, जिससे पानी बह जाता। मुँह ढँकने के लिए भी युक्ति सोच ली थी। सन् 1929 में कुछ समय तक बापू हिमालय के कौसानी नामक स्थान में थे, जहाँ सरदी और कुहरा दोनों की बहुतायत रहती। उस समय गरमी का मौसम था। बापू वहाँ बरामदे में सोते। साबरमती में उनकी खाट कुटिया (हृदयकुंज) और साबरमती नदी के बीच में किनारे के थोड़े-से मैदान में लगा करती। सन् 1929 में एक बार जाड़े के दिनों में वहाँ वे अपनी उक्त कुटिया के बरामदे में सोए थे। गोलमेज के समय लंदन में भयंकर शीत के समय बापू जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते। भारत से लंदन जाते समय समुद्री जहाज पर तीसरे दर्जे के यात्रियों की तरह खुले आकाश के नीचे बापू सोते। खुले डैक पर उन्होंने अपना आसन जमाया। वहीं उनका प्रार्थना, भजन, सूत्रयज्ञ आदि का क्रम चलता। समुद्री लहरों की ताल के साथ जहाज पर उनकी रामधुन चलती और शोरगुल के बीच भी वे लिखते-पढ़ते।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल करेंगे राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यो की 25 व 26 को समीक्षा

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन 25 जुलाई को राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों और 26 जुलाई को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य कार्यो की समीक्षा करेंगे। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहेंगे। बैठक दोनो दिन प्रातः 11 बजे से राजभवन में आयोजित होगी। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक (नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कौंसिल) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति आदि की समीक्षा भी की जायेगी। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य हुए एम.ओ.यू., अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की जानकारी भी ली जाएगी।

छत्तीसगढ़ में खुलेगा 17वां निजी विश्वविद्यालय

रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें श्री दावड़ा विश्वविद्यालय को प्रदेश के 17वें निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के प्रस्ताव का विपक्ष ने भी समर्थन किया। यह विश्वविद्यालय रायपुर के अभनपुर स्थित भेलवाडीह गांव में स्थापित किया जाएगा। इसमें पत्रकारिता, कला, विज्ञान, शिक्षा, होटल प्रबंधन, व्यावसायिक शिक्षा, एमफिल और पीएचडी के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी की बिगड़ी तबीयत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित तूता में आंदोलन कर रहे एक संविदा कर्मचारी अचानक बेहोश होकर मंच से गिर गया। तीन प्रदर्शनकारी नियमितीकरण की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसमें से एक की अचानक तबीयत खबर होने की वजह से वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए एंबुलेंस से अभनपुर अस्पताल भेजा गया है। धरना के दौरान बेहोश हुए संविदा कर्मचारी का नाम प्रेम राजपूत बताया जा रहा है। उसने पिछले 48 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। इससे शुगर और बीपी लेवल कम हो जाने से वह बेहोश हो गया। इस घटना को सुनकर वहां मौजूद लोगों में काफी देर तक अफरा-तफरी मच गई। उसके साथ आमरण अनशन पर बैठे दो और संविदा कर्मचारियों की भी तबीयत ठीक नहीं है। प्रदर्शनकारी के बेहोश होने से नारेबाजी और शोर शराबा से गूंजने वाले तूता में अचानक सन्नाटा छा गया। इस घटना के बाद धरने पर मौजद लोग असहज महसूस कर रहे हैं। फिर भी प्रदर्शनकारियों की जिद्द आंदोलन पर भारी है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक पर खरे उतरे छत्तीसगढ़ के 100 अस्पताल

रायपुर। पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 100 अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक पर खरे उतरे हैं। शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के 100 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। इनमें बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। राज्य के कई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2018 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त एक भी अस्पताल नहीं था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 में पहली बार प्रदेश के छह अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।

प्रदेश में फेक न्यूज फैलाया तो खैर नहीं आईजी ने सभी एसपी को दिए निर्देश

रायपुर। कुछ ना कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि वो समाज में जहर घोलने का काम करती है। सोशल मीडिया में ऐसे दुष्प्रचार को लेकर अब छत्तीसगढ़ पुलिस सतर्क हो गई है। विधानसभा चुनाव की करीब है। ऐसे वक्त में सोशल मीडिया में हेट स्पीच, अफवाह, फेक न्यूज की बाढ़ आ जाती है। लिहाजा अब रायपुर के रेंज आईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। रायपुर आईजी अजय यादव ने सभी एसपी को निर्देश जारी कर कहा कि सोशल मीडिया में प्रचारित अफवाहों या आपत्तिजनक पोस्ट से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। शांति व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। सभी जिलों में इसे लेकर सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है, जिसे और सशक्त बनाने के आईजी ने निर्देश दिए हैं। आईजी ने कहा कि वैसे पोस्ट जिससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है, आपत्तिजनक पोस्ट हो, समाज का माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे पोस्ट पर नजर रखें।

भाजयुमो ने किया व्यापमं कार्यालय का घेराव

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को भर्ती में भ्रष्टाचार के विरोध में व्यावसायिक परीक्षा मंडल कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान भारी संख्या में उपस्थित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गोबर और स्याही के माध्यम से अपना विरोध व्यापमं कार्यालय में दर्ज किया। आंदोलन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। इसके कारण कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी पहुँची। इस आंदोलन में भाजयुमो को उन युवाओं का भी साथ मिला जो व्यापम परीक्षाओं में हुई अनियमितता के चलते परेशान हैं।

भाजयुमो ने घेराव के बाद राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मोर्चा ने कई बिंदुओं पर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य के संपूर्ण जिलों में सहायक ग्रेड-3 / स्टेनोग्राफर तथा तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती बिना परीक्षा आयोजित किये जिलावार की जा रही है, जो कि अनुचित प्रक्रिया है। यह भर्तियाँ पूर्व में प्रदेश स्तर पर 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ व्यापमं के माध्यम से प्रतियोगी चयन परीक्षा के आधार पर होती रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने का दृश्य भी प्रकट हो रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की भर्ती में इंटरव्यू हेतु 35 लोगों को बुलाया जाता है और अंतिम चयन सूची में ऐसे 2 लोगों का नाम आता है, जिनका नाम पूर्व घोषित 35 उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा व्यापमं द्वारा ली गयी और परीक्षा का परिणाम भी व्यापमं को जारी करना था परन्तु पुलिस मुख्यालय द्वारा व्यापमं से बंद लिफ़ाफ़े में परिणाम अपने यहाँ मंगवा लिया गया जो कि अनुचित प्रक्रिया थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सहायक शिक्षक पद हेतु 1,83,281 आवेदन प्राप्त हुए। परीक्षा में 1,46,176 अभ्यर्थी शामिल हुए एवं अनुपस्थित 37,105 अभ्यर्थी थे। यह आँकड़ा व्यापमं द्वारा परीक्षा के तुरंत पश्चात जारी हुआ था। अंतिम परिणाम में जारी सूची में अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,275 हो गयी। अतिरिक्त 99 अभ्यर्थी की संख्या बढ़ना यह संदेह की स्थिति और भर्ती में भ्रष्टाचार का सूचक है।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को भूपेश बघेल की सरकार ने बर्बाद कर डाला है। हमारा राज्य प्रतिभावन युवाओं से भरा हुआ है जो देशभर के अलग-अलग जगह प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने अपने शासनकाल में प्रदेश के युवाओं का भविष्य अपनी भ्रष्ट नीति से बर्बाद कर दिया है। शुक्रवार को आहूत घेराव में भाजयुमो प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष व रायपुर संभाग प्रभारी रोहित माहेश्वरी, रीतेश मोहरे, खुशबू बंजारे, पियूष ठाकुर, शांतनु शुक्ला, प्रखर मिश्रा, अनुराग चौबे, समीर फ़रिकार, विकास मित्तल, अंजिनेश शुक्ला, दीक्षा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रायपुर गोविंदा गुप्ता, जिला अध्यक्ष बलौदाबाजार सुनील यदु, जिला अध्यक्ष रायपुर ग्रामीण फनेन्द्र वर्मा, जिला अध्यक्ष महासमुंद जसराज चंद्राकर, जिला अध्यक्ष गरियाबंद डॉ. योगिराज कश्यप, अर्पित सूर्यवंशी, राहुल राव, उत्कर्ष त्रिवेदी, साक्षी बघेल, ऋभुराज अग्रवाल, आदित्य मूंदड़ा, सोनू यादव, अनमोल तिवारी, आकाश शर्मा, नरेश पिल्लै, बिट्टू शर्मा, संदीप कसार, जितेंद्र देवांगन, अमित सिंघल, योगी साहू, प्रशांत यादव, राहुल यादव, आकाश तिवारी, गंधर्व पांडेय, धर्मेश साहू, करण कश्यप, ज्ञानप्रकाश चंद्राकर, अनमोल तिवारी, आवेश पांडे, शरद अग्रवाल, प्रतीक साहू, अखिल, आकाश तिवारी, अश्वनी विश्वकर्मा, आशीष आहुजा, विजय लहरवानी, वासु शर्मा, अनिल शर्मा, विकास शुक्ला, विशाल शुक्ला, रोहन सिंह, संजय जलक्षत्री, किशोर सोनी, अविनाश शर्मा, दीपक तन्ना, आलोक शर्मा, दीपक जायसवाल, अन्नु कवंर, मोहन पाठक, राज गायकवाड़, आशीष टोडर, श्रेणी बोथरा, शरद साहू, भरत कुंडे, आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार और उप अभियंता पर लगाया अर्थदंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने पर दो जन सूचना अधिकारियों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के निराकरण में लापरवाही बरतने और समय सीमा में क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर संबंधित जनसूचना अधिकारियों पर यह अर्थदंड लगाया है। एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि रायपुर तहसील के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को मार्च 2019 में आवेदक द्वारा सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का अवलोकन करने का आवेदन दिया गया था। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा 3 वर्ष विलंब से आवेदक को अवलोकन के लिए सूचना जारी किया गया। इस संबंध में आयोग के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसका कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण से तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर एवं वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर श्री अमित बेक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

एक अन्य प्रकरण में नगर पालिका रतनपुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी द्वारा नामांतरण संबंधी फाइलों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आवेदक के द्वारा चाहे जाने के विषय पर मूल आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं करने और आयोग को जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं उप अभियंता एवं वर्तमान में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ श्री देवेंद्र पहाड़ी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा करने के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारियों के नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने मणिपुर हिंसा को लेकर निकाली मशाल रैली

बिलासपुर। शहर में पिछले दो माह से मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर मशाल रैली निकाली गई। आप के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम को बिलासपुर के देवकीनंदन चौक से रैली निकालकर अपना विरोध जताया। साथ ही उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मणिपुर सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है।

मणिपुर सरकार को ठहराया दोषी- कुछ दिन पहले वायरल वीडियो में मणिपुर की दो महिलाओं को बंधक बनाकर नग्न अवस्था में घुमाने का मामला सामने आया था। आम आदमी पार्टी ने मामले में मणिपुर सरकार को दोषी ठहराते हुए बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाया है। 4 मई का यह वीडियो कांगपोकपी जिले के बी। फैनोम गांव की है, जहां पूरे गांव को जलाने के बाद दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

पूरे देश में घटना को लेकर कार्रवाई की मांग- इस वीडियो को लेकर पूरे देश में लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही महिला उत्थान पर काम करने वाली संस्थाएं इस घटना को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

आप के जिला अध्यक्ष खगेश चंद्राकर ने कहा सभी देशवासी असहाय महिलाओं की वीभत्स वायरल वीडियो को और वायरल न करें। वीडियो को शेयर करे बिना ही इस घृणित कृत्य के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें।

मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग- आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने मामले को लेकर मणिपुर सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने इस भयावह और उत्पीड़न की घटना की निंदा की है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से मणिपुर सरकार की बर्खास्त करने की मांग की है।

आज रायपुर आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री शाह

- **एक महीने के अंदर तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा**

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री और छत्तीसगढ़ के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह आज रायपुर आएंगे। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमरतराई में प्रदेश के बीजेपी नेताओं की हाई लेवल बैठक ले सकते हैं। इसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

चर्चा है कि केंद्रीय गृहमंत्री के साथ एक प्राइवेट सर्वे एजेंसी के कुछ लोग भी आएंगे। खबर है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। कल सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। बीजेपी 2023 के चुनाव को जीतने में लगी है। इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यही वजह है कि शाह एक महीने के अंदर तीसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने 5 जुलाई को रायपुर में बीजेपी नेताओं के बैठक ली थी। रात्रि विश्राम के बाद सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना हो गए थे। इस दौरान वो छत्तीसगढ़ भाजपा की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं दिखे थे।

शाह बीजेपी के कमजोर सीटों पर फोकस करेंगे। पांच जुलाई को अपने दौरे के दौरान दिए गए होमवर्क की जांच करेंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल होंगे। शाह की तीसरी बैठक में जवाब देने के लिए प्रदेश के भाजपा नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर इस काम में जी जान से लगे हुए हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री लगातार चुनावी वाले राज्यों पर अपनी नजर रखे हुए हैं। लगातार दौरा कर बीजेपी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं।

कमजोर वाली सीटों का होगा आकलन

चुनाव में बीजेपी की नैया पार करने के लिए शाह ने प्रदेश के नेताओं को होमवर्क दिया है। सूत्रों के अनुसार, रायपुर दौरे से रवाना होने से पहले शाह ने प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नबीन को एक प्रारूप पर काम करने के लिए कहा है। इसके आधार पर हर विधानसभा की जानकारी जुटानी है। इसके बाद शाह दोबारा चर्चा करेंगे। पार्टी नेताओं को विधानसभावार रिपोर्ट तैयार रखने के लिए कहा गया है। इसमें यह देखा जाएगा कि बीजेपी किस विधानसभा में मजबूत है और किसमें कमजोर स्थिति में है। इसका आकलन किया जाएगा। वहीं जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, उसकी वजह भी बताने के लिए कहा गया है।

अजय जामवाल को टॉस्क दिया

वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा करते हुए चुनावी तैयारियों की भी जानकारी ली। 10 दिन के अंदर चुनावी रणनीति बनाकर शेयर करने के लिए कहा गया है। इसमें हर सीट पर भाजपा की स्थिति और आगामी प्लान क्या होगा, इसका जिक्र रहेगा। इसके लिए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को टॉस्क दिया गया है।

गोबर घोटाला, चारा घोटाला से भी बड़ा: सौरभ सिंह

- **जिनके घर गाय नहीं, उनसे 2 लाख किलो गोबर खरीदा, 5 लाख से ज्यादा किया भुगतान**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आखिरी दिन की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल में सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह ठाकुर ने पत्थलगांव विधानसभा में रेडी टू ईट का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि रेडी टू ईट के लिए सामाग्री की सप्लाई कौन करता है। किसको ठेका दिया गया है। इस पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि राज बीज विकास निगम रेडी टू ईट के सामग्री की सप्लाई करती है और गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति को ठेका दिया गया है। रामपुकार ने कहा कि ये शायद बाहर का है।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गोठान का मामला उठाया। स्वीकृत गोठानों और पूर्ण, अपूर्ण गोठानों की जानकारी मांगी। गोठानों में सुविधाओं और गोबर खरीदी को लेकर सवाल पूछा। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 10240 गोठान पूर्ण कर दिए गए हैं। अपूर्ण गोठान जमीन आदि मामलों के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है।

ताम्रध्वज साहू ने गोबर खरीदी को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2023 तक 1 करोड़, 23 लाख, 19 हज़ार 8 सौ 45 क्विंटल गोबर पशुपालकों से खरीदा गया। इस पर अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने गोबर खरीदी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि 229 करोड़ कहां पर बैलेंस है? या तो फर्जी खरीदी की गई है। 229 करोड़ का हिसाब नहीं आ रहा है। ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। सौरभ सिंह ने कहा अकलतरा में तीन महिलाओं से दो लाख 82 हजार किलो गोबर खरीदा गया। तीनों महिलाएं एक परिवार की हैं। उनके यहां गाय नहीं है। ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है।

बाल पत्रिका किलोल की खरीदी पर विस में हुआ शोर-शराबा

- **महंत ने सरकार से एक हफ्ते के भीतर मांगी रिपोर्ट**

रायपुर। सरकारी स्कूलों में बाल पत्रिका किलोल की खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को जमकर शोर शराबा हुआ। पत्रिका की खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे करने का आरोप विपक्ष ने लगाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने एक हफ्ते के भीतर किलोल पत्रिका की खरीदी से जुड़े तमाम जानकारियों की रिपार्ट स्कूल शिक्षा मंत्री से मांगी है।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि स्कूलों में मासिक बाल पत्रिका, और अन्य पत्रिका खरीदी के लिए प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा द्वारा आदेश जारी किए गए। पत्रिकाओं की खरीदी के लिए सीआरसी अनुदान राशि के उपयोग करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि सभी स्कूलों में बाल पत्रिका की आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए संकुल समन्वयकों द्वारा अपने संकुल की शालाओं में बच्चों को पत्रिका के विभिन्न गीत, कविता, कहानियों का वाचन करवाते हुए परीक्षण करवाया जाए। साथ ही संकुल के बच्चों और शिक्षकों को पत्रिका में अपनी आलेख भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए राज्य में प्रत्येक मासिक पत्रिका किलोल की आजीवन सदस्यता के लिए 10 हजार रुपए व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री चंद्राकर ने पूछा कि किलोल पत्रिका की खरीदी के लिए निर्देश जारी हुए हैं, या अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं? इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी पत्रिकाओं के खरीदने के लिए आदेश दिए गए हैं। इस पर पूर्व मंत्री ने किलोल, और अन्य पत्रिकाओं की खरीदी के लिए नियम और प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा रायपुर द्वारा निर्देश जारी किया गया। स्कूलों में इस तरह की खरीदी की जाती है।

श्री चौबे ने पिछली सरकार में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अन्य की किताबें खरीदी गई थी। पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि वो स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, और पिछले सरकार के समय की खरीदी की जांच की भी चुनौती दी। श्री चंद्राकर ने कहा कि निजी लोगों पर भी दबाव डालकर किलोल पत्रिका खरीदवाई गई है। पूर्व मंत्री ने यह भी पूछा कि कितने बच्चों के पत्रिका में आलेख छपे हैं? सदस्य धर्मजीत सिंह ने किलोल पत्रिका खरीदी के लिए आपराधिक कृत्य की आशंका जताई, और कहा कि किलोल की खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए हैं। यदि पुस्तक छपना बंद हो जाए, तो क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हस्तक्षेप कर कहा कि उन्हें (डॉ. महंत) एक हफ्ते के भीतर किलोल पत्रिका खरीदी सहित तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

खोखला अविश्वास प्रस्ताव है, आरोप पत्र असत्य का पुलिंदा : चौबे

रायपुर। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा काफी लंबा चला। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा ने 109 बिंदुओं के आरोप पत्र पेश किया है, उसमें से केवल एक चर्चा की, बाकी इधर-उधर की बात की है। खोखला अविश्वास प्रस्ताव है,आरोप पत्र असत्य का पुलिंदा हैं। हालांकि रेडी टू ईटी, बीज, स्कूल भवन, गौठान के साथ कई मुद्दों पर विपक्ष, सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल दागते रही।

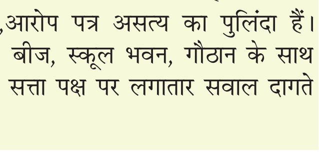

तुम्हें बस यह बताना चाहता हूँ.....

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज़ था, जो नरेंद्र मोदी के नौ सालों में बढ़ कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया। कर्ज भी बढ़ गया,रियायतें भी घट गई, नौकरियां भी कम हो गई, लघु तथा मध्यम उद्योग तबाह हो रहे हैं,सरकारी कंपनिया बिक रही हैं..आखिर यह सब धन, जा कहां रहा है सरकार...?

पीएम मोदी को छोड़कर सभी 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का

कर्ज लिया। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया है। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है।% इसके बाद से ही भारत सरकार के कर्ज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने कितने कर्ज लिए और ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। केंद्रीय सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है इसके अलावा 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल का लिखित जवाब दिया है। सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कहा कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181त्न कर्ज बढ़ा है।2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक तीन गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2014-15 के मुताबिक तब भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में देश की जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाए तो उस समय हर भारतीय पर औसत कर्ज करीब 42 हजार रुपए था।अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान लें तो आज के समय में हर भारतीय पर 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज है।इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। अब 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गये...!

अब इंडिया गुलामियत का प्रतीक......

भारत की 26 विपक्षी पार्टियों ने अपने नये संगठन का नाम इंडिया (i-n-d-i-a)रखा है,इसे भाजपा के कुछ लोग गुलामियत का प्रतीक ठहरा रहे हैं,वैसे पीएम नरेन्द्र मोदी के सोशल मिडिया प्रोफ़ाइल/हेंडल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के

सोशल मिडिया प्रोफ़ाइल में बीजेपी4 इंडिया लिखा है......! इधर नरेंद्र मोदी सरकार ने कई योजनाओं के नाम में इंडिया शामिल किया था मसलन स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किलइंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया और बढेगा इंडिया आदि आदि.....? इसका क्या मतलब निकाला जाए....!

किसानों के बाद कर्मियों पर भी भूपेश बघेल मेहरबान...

किसानों, गरीबों के लिये बड़े कदम उठानेवाली छग की भूपेश सरकार ने मौजूदा विधानसभा के

आखिरी सत्र कर्मचारियों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया है। शासकीय कर्मियों के लिए चार प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने का ऐलान किया है। सरकारी कर्मियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की गई हैं।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ पंचायत सचिवों को भी विशेष भत्ता मिलेगा। संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मियों को 27 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान भीकिया। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हर महीने 2 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता देगी। इसके साथ-साथ पंचायत सचिवों को भी विशेष भत्ता दिया जाएगा। 15 साल से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को 2500 रुपये और इससे अधिक सेवाकाल वालों को 3000 रुपये विशेष भत्ता मिलेगा।सरकार ने दैनिक वेतनभोगी के वेतन में 4000 रुपये मासिक वृद्धि का निर्णय भी लिया है। इसके साथ-साथ सभी शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9 प्रतिशत और सी तथा अन्य शहरों के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।

छ्ग के वरिष्ठ आईपीएस (एडीजी) जीपी सिंह बर्खास्त...

आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित छ्ग के वरिष्ठ आईपीएस, एडीजी,जीपी सिंह को केंद्र सरकार ने

राज्य सरकार की अनुशंसा पर बर्खास्त कर दिया है।1 जुलाई 2021 की सुबह एसीबी - इओडब्लू की टीमों ने रायपुर,राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था,जिसमें करीब 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था।इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे।जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था।जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी थी,मामला कोर्ट में विचाराधीन है।आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण दर्ज है।

बस्तर दशहरा इस बार 107 दिनों का ...

बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा इस बार 75 दिनों की बजाए 107 दिनों का होगा। इसकी शुरुआत 17 जुलाई से हरेली के साथ शुरू हो गई है। इस वर्ष 2023 में एक माह तक का पुरुषोत्तम/ अधिकमास पड़ने और 28 अक्टूबर को ग्रहण होने के कारण दशहरा पर्व की समय सीमा बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि बस्तर के आदिवासियों की आराधना देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने हेतु हर साल देश विदेश? भक्त और पर्यटक पहुंचते हैं। बस्तर दशहरा के ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार वर्ष 1408 में बस्तर के काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथपुरी में रथपति की उपाधि दिया गया था तथा उन्हें 16 पहियों वाला एक विशाल रथ भेंट किया गया था। इस तरह बस्तर में 615 सालों से दशहरा मनाया जा रहा है।

और अब बस....

- मणिपुर के हालात की तुलना छ्ग से करने के पीछे आखिर पीएम की क्या मंशा है...?
- विधानसभा के पास नग्न प्रदर्शन करने के पीछे आखिर है कौन...?
- छ्ग के सीएस अभिताभ जैन ने फर्जी प्रमाणपत्र के जरिये नौकरी करनेवालों को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिये हैं।
- विस सत्र के बाद 2अगस्त के पहले कुछ कलेक्टरों को इधर उधर करने की चर्चा तेज है।

इधर उधर की बात छोड़ भूपेश जी बताए प्रदेश के हालात : साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के हालात दिनों-दिन दयनीय होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार अपने राज्य के हालात तो सुधार नहीं पा रही है, दूसरे राज्यों के मामलों में दखल देकर सियासी ड्रामा खेलने में मशगूल है। श्री साव ने कहा कि ऐसा एक भी सकारात्मक काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे शासनकाल में नहीं किया जिसे प्रदेश में विकास, बेहतर शिक्षा, शांति-व्यवस्था, सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के मोर्चे पर वह गिना सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पूरे शासनकाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को अपने राजनीतिक दुराग्रह का शिकार बनाने का

काम किया। किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के साथ जिस तरह छल-प्रपंच करके वादाखिलाफी की गई, उसकी शायद ही कोई और मिसाल कहीं देखने को मिले। श्री साव ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के नाम पर तो युवाओं को ठगा ही गया, अपने हक की लड़ाई में न्याय नहीं मिल पाने की इन युवाओं की पीड़ा और समस्या पर भी प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे अफसरों-कर्मियों पर कांग्रेस सरकार ने पूरे शासनकाल में कोई कार्रवाई नहीं की और अंततः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के युवकों को अपनी मांग के लिए विधानसभा मार्ग पर पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ा। प्रदेश सरकार बजाय इस घटना पर शर्म महसूस करने के आंदोलित युवाओं को अपराधी घोषित करने में लगी है। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा? श्री साव ने कहा कि नग्न प्रदर्शन की घटना से प्रदेश शर्मसार हुआ है जिसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि प्रदेश भर में पिछले 5 वर्षों में कुल 39,267 बच्चों की मौत हो गई। उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में अपने लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया है। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बच्चों की मौत पर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही।

टापर्स टाक शो में मिला सफल होने का तरीका

- यूपीएससी टॉपर्स ने दिए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब

रायपुर। जिला प्रशासन द्वारा आज राजधानी रायपुर के दीन दयाल ऑडिटोरियम में टॉपर्स टॉक के दौरान यूपीएससी परीक्षा के टॉपर्स ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से संबंधित सवालों के जवाब दिए।टापर्स से सवाल जवाब के दौरान रायपुर के अभ्यर्थी मिहिर सिन्हा ने टापर्स से पूछा कि एनसीईआरटी की किताबों को कैसे पढ़ें। इस सवाल के जवाब में टापर्स ने कहा कि एनसीईआरटी की 10वीं से 12वीं कक्षा की किताबें महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र की अच्छी जानकारी मिलती है। अतः इन्हें पढ़ना जरूरी है।

प्रतिभागी आर्ची जैन के नोट्स बनाने के एक सवाल का जवाब देते हुए टॉपर्स ने कहा कि नोट्स का मकसद ये होता है कि जब हम कुछ भूलें तो इसे देखकर वो तथ्य याद कर लें। उन्होंने कहा कि नोट्स में वहीं तथ्य होने चाहिए जिन्हें याद करने में कठिनाई होती हो।

आनलाइन या आफलाइन कोचिंग में से क्या बेहतर है, इस सवाल का जवाब देते हुए टापर्स ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी क्षमता और सहुलियत के अनुसार कोचिंग करनी चाहिए। फिर चाहे आफलाईन हो या ऑनलाईन इससे फर्क नहीं पड़ता। टॉपर्स ने ये भी कहा कि कोचिंग करना भी अनिवार्य नहीं है। यदि कोई परीक्षा का जानकार व्यक्ति सही मार्गदर्शन दिखाए तो भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यूपीएससी में रैंक-1 हासिल करने वाली इशिता किशोर ने कहा कि मैंने कारपोरेट सेक्टर में काम किया। पिता वायु सेना में थे, उन्हीं से प्रेरणा मिली कि देश के लिए कुछ करना है। मैंने सिविल सेवा को चुना। परीक्षा की तैयारी शुरू कि तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पढ़ते गई, आगे बढ़ते गई और चीजें आसान होती चली गई। प्रतिभागियों से सवाल जवाब के दौरान रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा तथा सहायक कलेक्टर श्री जयंत नहाटा टॉपर्स टॉक समारोह में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा आदतन शांति विरोधी : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, सयान और जवान खुशहाल हैं। भाजपा

के शासन काल में हालात बद से बदतर थे। चौतरफा लूटमार मची थी। गरीबों का जीना दूभर था। महिलाओं बेटियों की आबरू सामूहिक रूप से लूटी जाती थी। झलियामारी कांड होते थे। आंखफोड़वा कांड होते थे। गर्भाशय कांड होते थे। नक्सल हिंसा चरम पर थी और निर्दोष आदिवासियों पर जुल्म ढाए जाते थे। उनके घरों की महिलाओं से पुलिस दुष्कर्म करती थी। बदलाव के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने हालात बदल दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में कानून का राज चल रहा है।भाजपा जहां भी सत्ता में होती है, वहां वर्ग संघर्ष कराती है। फूट डालो, राज करो की नीति अंग्रेजों के मुखबिरों के डीएनए में कूट कूट कर भरी हुई है। आज मणिपुर जल रहा है, इनकी वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाशा देख रही है।

कांग्रेस राज में कम हुआ शराब की खपतः आनंद शुक्ला

रायपुर। कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में शराब की खपत में कमी आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण कर प्रदेश में शराब की खपत को बढ़ावा

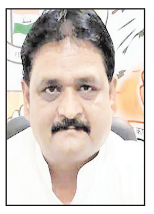

दिया। भाजपा सरकार का उद्देश्य शराब से राजस्व को बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमाना था। रमन राज छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में गोवा के बाद पहले नंबर पर था, कांग्रेस सरकार के पांच सालों में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ 18वें नंबर पर आ गया है। राज्य में शराब की खपत कम करने कांग्रेस सरकार ने 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया। आज छत्तीसगढ़ में 2018 की अपेक्षा अंग्रेजी शराब की खपत में 15 फीसदी और देशी शराब की खपत में 10 प्रतिशत की कमी आई है। शराब का सरकारीकरण क्यों किया था? आखिर वह कौन से कारण थे जिसके चलते शराब बिक्री का व्यवसाय निजी हाथों से छीनकर सरकारी हाथों में लेना पड़ा? रमन राज के 15 साल में प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी क्यों हुई थी।

युवाओं से किए खिलवाड़ कांग्रेस जवाब दे : चौधरी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार को यूपीएससी के टॉपर्स को राजधानी बुलाकर वर्कशॉप कराए जाने पर तंज कसा है। श्री चौधरी ने कहा कि पिछले पौने पाँच सालों में

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भर्ती में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापमं में माफिया राज चलाया है। पीएससी में पैसा और परिवार चला है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़िया युवा भाई-बहनों के मन में जो दर्द है, उस दर्द का ज़वाब कौन देगा? उन सवालों का ज़वाब कौन देगा? भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि लवासना में पहले कहा जाता था कि एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ को आप कुछ भी कंसीडर करिए, आईएएस के अच्छे काम करने की दृष्टि से काडर के तौर पर एक बेहतरीन काडर कहा जाता था। भूपेश सरकार ने प्रदेश की इतनी दुर्गति की कि अब कहा जाता है कि आईएएस के काम करने की दृष्टि से यह एक सबसे बदतरीन काडर है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से तबादला उद्योग चला है।

कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। सुबह से बदल छाए हुए हैं। इससे उमस वाली गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। प्रदेश में अभी खंड वर्षा हो रही है। लोग तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात पड़ने की संभावना है। प्रदेश के 4 जिलों में जैसे- सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। दो दिनों बाद प्रदेश के कई जगहों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, रायपुर, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे ओडिशा तट पर स्थित कम दबाव के वाले क्षेत्र के केंद्र और उसके बाद पूर्व-दक्षिणपूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उपर एक कम दबाव का क्षेत्र और उससे सटे ओडिशा तट के आसपास के क्षेत्र में देवा स्थित चक्रवाती सिस्टम समुद्र तल से 76 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। एक हवा का शियर जोन 20 डिग्री उत्तर में 3.1 किमी से 7.6 किमी ऊंचाई तक विस्तारित है।

नरेंद्र मोदी जी उत्तरदायित्व निभाने में नाकाम रहा हैः वंदना

रायपुर। मणिपुर की घटना पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना को देखकर हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घूमाया जाता हैं और सामूहिक

बलात्कार किया जाता है वह बेहद शर्मनाक और मानवता को तार-तार कर देने वाला है। और ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटी होगी जिनको सामने भी नहीं लाया गया है। मणिपुर में हुई घटना से पूरा देश स्तब्ध है यही है भाजपा पाखंडियों का विकास मॉडल इस अत्यंत नाकाम और अराजकतावादी सरकार ने सारी हदें पार कर दी है लेकिन नरेंद्र मोदी और मणिपुर सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पिछले 90 दिनों से मणिपुर में हिंसा हो रही थी प्रधानमंत्री जी, मणिपुर के भाजपा के राज्य सरकार मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे। नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश पूछ रहा है बेटी बचाओ का जो नारा था क्या भारत वासियों के लिए यह चेतावनी था आज बेटियों का अस्तित्व ही संकट में आ गया है।

समाज में बदलाव लाने में समाचार पत्रों की महती भूमिका : श्री हरिचंदन

- ऑल इंडिया लघु एवं मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन आज भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया लघु एवं मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए समाचार पत्रों की महती भूमिका है।

राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लघु समाचार पत्रों का योगदान भुलाया नही जा सकता। आजादी के लिए जागरूकता और उत्साह भरने और एकजुट होकर लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन लघु समाचार पत्र ने किया। महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित ''हरिजन'' पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई। यंग इंडिया जैसी पत्रिकाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करती थीं।

राज्यपाल ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में प्रेस की महती भूमिका है। संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लोगों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब लोगों के मुलभूत अधिकारों का हनन होता है तो शोषण के खिलाफ लड़ने और लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।राज्यपाल ने कहा कि यह सम्मेलन समाचार पत्रों के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका धारको को और पत्रकारों के बीच ज्ञान विनिमय के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। उन्होंने आग्रह किया कि इस सम्मेलन में देश की समस्याओं पर भी चर्चा करें। अपने समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रीत करें और समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रहें। समाज मे व्याप्त विषमता, भ्रष्टाचार, शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर अपने लेखो के माध्यम से चर्चा करें और लोगों को समाधान के लिए प्रेरित करें।इस अवसर पर फेडरेशन के पदाधिकारी एवं देश भर से आये हुए विभिन्न लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संस्थाओं के मालिक संपादक, और प्रकाशक उपस्थित थे। राज्यपाल ने फेडरेशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।

पेंशनरों को महंगाई राहत देने के मामलें में मुख्यमन्त्री बघेल की चुप्पी से हैरानी

रायपुर । विधान सभा में कर्मचारी संवर्ग के लिए केन्द्र के बराबर डी ए और अन्य लोगो को भी आर्थिक लाभ की घोषणा के बाद छ ग कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल का विधान सभा परिसर में प्रत्यक्ष भेंट कर खूब स्वागत किया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा ने राज्य के पेंशनरों को भी 9 प्रतिशत महंगाई राहत का मामला लम्बित रहने पर चर्चा करते हुए पेंशनरों के लिए भी आदेश जारी करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया परंतु मुख्यमन्त्री इस विषय पर चुप्पी साधे रहे। उनके द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करने पर सब बहुत हैरान हुए। चूकिं वहाँ भेंट मुलाकात करने वालों बहुत अधिक भीड़ होने के कारण आगे और चर्चा सम्भव नहीं हो सकी। ऐसा वहाँ प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर्मचारी नेताओं ने बताया। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया है कि म प्र शासन ने छ ग शासन को मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के बाध्यता का हवाला देते हुए 30 जनवरी 23 को पत्र भेज कर सहमति मांगी है, परंतु सरकार 6 माह से उक्त पत्र को दबाये बैठी है और सहमति देने में जानबूझकर कर विलम्ब कर रही है।मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 जून 23 को पुनः पत्र भेजकर सहमति चाहा है परंतु छ ग शासन अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.